राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 02 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-272 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बंजर जमीनों को हरा-भरा बना रहे गोवा के किसान

खेती की नई शुरुआत, जर्मन विशेषज्ञो की ले रहे मदद

पणजी (एजेंसी)। गोवा के कृषि क्षेत्र में जल्द ही एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। बिचोलिम की किसान उत्पादक संस्था ने अपनी बंजर और खाली पड़ी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए जर्मनी की आधुनिक कृषि तकनीकों और टिकाऊ खेती के तरीकों से प्रेरणा लेने का फैसला किया है। इस योजना के तहत किसान ने 1200 हेक्टेयर बंजर जमीन पर खेती



शुरू करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसके लिए जर्मन एक्सपर्ट्स की तकनीकी मदद से आधुनिक मशीनों से खेती और एग्रो-टूरिज्म (कृषि पर्यटन) की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों के लिए जर्मन विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा आयोजित चार दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जर्मनी में अपनाई जाने वाली आधुनिक कृषि पद्धतियों, मशीनीकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग और टिकाऊ खेती के बुनियादी ढांचे को कृषि अधिकारियों को समझाना था।

अब आजम खान के परिवार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

जौहर यूनिवर्सिटी में सचिव पत्नी-कोषाध्यक्ष बहन पर ईडी की टेढ़ी नजर

रामपुर (एजेंसी)। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सपा नेता आजम खां को गिरफ्तार किया है। उन पर जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में 400 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी और 80 करोड़ से अधिक सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। इसी प्रकरण में आजम के साथ जौहर ट्रस्ट को भी नामजद किया गया है जिसमें उनकी



पत्नी, दोनों बेटे और बहन आदि भी शामिल हैं। यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ने पर आजम के स्वजन भी मुसीबत में फंस सकते हैं। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को अजीम नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद जौहर ट्रस्ट के जरिए ही जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। निजी विश्वविद्यालय में सरकारी धन का उपयोग हो या फर्जी फर्मों से चंदा लेने की बात, सब कुछ इसी ट्रस्ट के जरिये किया गया है। ऐसे में ट्रस्ट में शामिल सभी सदस्यों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

मोदी को हटाएंगे, तभी लोकतंत्र बचेगा

रामलीला मैदान से सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे कहा-ज्ञानेश कुमार छोड़ेंगे नहीं ,मोदी को जाना ही होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के विरोध में इंडिया ब्लॉक की रैली हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पाताल में क्यों न चले जाएं, हम उन्हें वहां से भी खोज लाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी आज लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद वोट चुन रहे हैं। उनको वोट कौन देगा वे वोटर्स चुनते हैं। आज की केंद्र सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार, ये सब चोरी की सरकार हैं। इन चोरों को निकालना है। इस रैली में मंच पर राहुल गांधी,अखिलेश यादव समेत 19 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इससे पहले विपक्ष का मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो जंक्शन से शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे रामलीला मैदान पहुंचा।



खड़गे का आरोप मोदी अपना वोट खुद चुन रहे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि मोदी आज लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद वोट चुन रहे हैं। उनको वोट कौन देगा, वे वोटर्स चुनते हैं। आज की केंद्र सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार, ये सब चोरी की सरकार हैं। इन चोरों को निकालना है। चोरों की सरकार हर जगह बैठी है, आपका सपोर्ट हम चाहते हैं। मोदी जाएंगे तो ही लोकतंत्र बचेगा। मोदी को हटाओ, लोकतंत्र को बचाओ।

अखिलेश यादव बोले-काशी की जनता ने उन्हें डबल जीरो दिया

अखिलेश ने कहा, मैं देख रहा हूं कि रामलीला मैदान में जो आवाज उठ रही है। गठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर लोकतंत्र को खत्म करने वालों के खिलाफ हुए हैं। आज जब सभा यहां होने जा रही थी उसी समय यूपी में भाजपा की तरफ से कहा गया कि एक करोड़ वोट हिंदू भाइयों के वोट काट दिए गए। उन्होंने कहा-अब उनको भी याद आ रहा है कि उनके वोट भी कट गए हैं। मतलब 31 हजार वोट हर विधानसभा में कम हुए हैं। जब जमीन ही नहीं बची तो अंगद का पैर कहां रखोगे। काशी की जनता ने उन्हें डबल जीरो दिया है।

पंजाब में एएपी को झटका 2 एमएलए ने पार्टी छोड़ी

दोनों एएपी एमएलए बीजेपी में हो सकते हैं शामिल

पटियाला (एजेंसी)। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद 2 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पटियाला के समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा शामिल हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने की वजह बताने के लिए चंडीगढ़ में साढ़े 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जौड़ामाजरा एएपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं लेकिन कुछ समय पहले पार्टी ने पूर्व अकाली नेता सुरजीत सिंह रखड़ा को उनकी जगह पर समाना विधानसभा सीट का हलका इंचार्ज बना दिया था। वहीं, हरमीत सिंह पठानमाजरा पर रेप का केस दर्ज हुआ था। जिसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया फरार हो गए थे। जांच में शामिल होने के लिए लौटने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एएपी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि अब भाजपा निष्कासित लोगों को इकट्ठा कर रही है।



बंगाल की खाड़ी में फिर बना नया चक्रवात

3 नवंबर को आंध्र के तट से टकराएगा मुरासु एक हफ्ते में दूसरा साइक्लोन,ओडिशा में बाढ़

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र मुरासु नाम के चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटे और झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। एक हफ्ते के भीतर बंगाल की खाड़ी में यह दूसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले 26 अक्टूबर को चक्रवात 'अर्नब' उठा था। यह 28 अक्टूबर को आंध्र के तट से टकराया था। इसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई थी। ओडिशा के गंजाम और गजपति जिले में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य अभी चक्रवात 'अर्नब' से हुए नुकसान से उबर ही रहा है। नए तूफान के कारण फिर से भारी बारिश हो सकती है। खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने निचले और पहाड़ी इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है।

लखनऊ समेत 10 शहरों में कोहरा छाया, ठंड बढ़ी

यूपी में 'अर्नब' तूफान के असर से 3 दिन लगातार हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिन का तापमान 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। रविवार सुबह लखनऊ, सहारनपुर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर समेत 10 शहरों में कोहरा छाया रहा। सड़कों पर सन्नाटा दिखा और 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया। इधर, वाराणसी, कानपुर और उन्नाव समेत 15 से ज्यादा शहरों में बादल छाए हैं। ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास करा रही हैं। दुकानों पर लोग अलाव सेकते नजर आ रहे हैं। आज बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में हल्की बारिश का अलर्ट है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया- यूपी में चक्रवात का असर अब खत्म हो गया है।



राजस्थान में दिन गर्म रात में सर्दी तेज

राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर शनिवार से खत्म हो गया। अब अगले 3-4 दिन तक आसमान साफ रहने की संभावना है। इससे पहले शनिवार को मौसम साफ रहा। हालांकि, सुबह के समय कई जिलों में हल्का कोहरा रहा। जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। पिछले 24 घंटे अधिकतम तापमान में भले ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं, रात के तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई। सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में रहा। शनिवार को सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही। हालांकि, बीते चार-पांच दिन में यहां के तापमान में तीन-चार डिग्री की गिरावट हुई है। फिर भी दिन का पारा करीब 35 डिग्री के करीब ही दर्ज हो रहा है। वहीं, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

12 साल में 49 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं बाहर

पीएम मोदी बोले-देश में आर्थिक असमानता भी घटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने कहा कि 2011 से 2023 के बीच भारत में 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इस दौरान देश में अत्यधिक गरीबी की दर 90 फीसदी तक कम हुई। मोदी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गरीबी खत्म करना सरकार के लिए सिर्फ नारा नहीं, बल्कि पक्का संकल्प है। मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 6 साल में रोजगार के 13.4 करोड़ नए अवसर बने हैं। यह संख्या कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी से करीब दोगुनी है। उन्होंने देश में आर्थिक असमानता कम होने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने ये आंकड़े इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए साझा किए।



गरीबी खत्म करना सरकार के लिए सिर्फ एक नारा नहीं

वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ नाम से रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 में 27.1 फीसदी थी, जो 2023 में घटकर 2.6 फीसदी रह गई। मोदी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है। उन्होंने आर्थिक असमानता मापने वाले गिनी इंडेक्स का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इसमें 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है और यह घटकर 23.0 पर पहुंच गया है।

3 वजहः खपत बढ़ी महिलाओं को मिला रोजगार

आम लोगों की कमाई और खर्च करने की क्षमता में सुधार हुआ है। 2017 से 2023 के बीच करीब 13.4 करोड़ नए रोजगार के अवसर बने। इनमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। कई महिलाएं पहली बार कमाई वाले कामों से जुड़ीं। मुफ्त राशन और सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने जैसी योजनाओं से गरीब परिवारों को सहारा मिला। गरीबी में कमी सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रही। लोगों के रहन-सहन और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है। अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों के पास पक्के मकान, बिजली, साफ पानी, शौचालय और रसोई गैस जैसी सुविधाएं हैं। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 2005-06 में देश की 53.8 फीसदी आबादी इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। 2019-21 तक यह आंकड़ा घटकर 16.4 फीसदी रह गया। वहीं, वर्ल्ड बैंक के पैमाने के अनुसार 22-23 में गरीबी घटकर 15.5 फीसदी रह गई है।

अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस को दिया राष्ट्रपति ध्वज

बोले-जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया,देशभर में कायम की मिसाल

चंडीगढ़ (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। शाह ने चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे तरीके से निभाई हैं। चंडीगढ़ ने देशभर की पुलिस के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि 1966 से चंडीगढ़ पुलिस शहर की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और उसने देश में पुलिस व्यवस्था के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय लिखा है।



अमित शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि इन 60 वर्ष में उत्तरी क्षेत्र के केंद्र के रूप में चंडीगढ़ ने पूरे भारत की सुरक्षा में योगदान देने का सफल प्रयास किया है। अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया जाना छह दशकों की सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता का सम्मान है।

राहुल विदेशी ताकतों की टूलकिट बनकर काम कर रहे

नड्डा बोले-आज के दिन ही सिखों का नरसंहार हुआ था

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में रैली के विरोध में भाजपा ने आज दिल्ली समेत देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च निकाला। दिल्ली में हरि नगर से तिलक नगर तक करीब एक किमी लंबा मार्च निकाला गया। इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवार और सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली के लिए 1 नवंबर का दिन जानबूझकर चुना है। 1 नवंबर 1984 को सिख विरोधी हिंसा हुई थी। वहीं, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हरियाणा के रोहतक में रैली निकाली। उन्होंने कहा



कि वोट चोरी कांग्रेस की विरासत है। ये वोट चोरी भी करते हैं और जनता के वोट का अपमान भी करते हैं। राहुल गांधी विदेशी ताकतों की टूलकिट बनकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज सिख विरोधी हिंसा के पीड़ितों को याद करना चाहिए था लेकिन राहुल गांधी उन्हें भूलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं।

राहुल देश के लोकतंत्र को चुनौती देना चाहते हैं

नितिन नवीन ने कहा- राहुल गांधी विदेशी ताकतों की टूलकिट बनकर काम कर रहे हैं। वे विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के लोकतंत्र को चुनौती देना चाहते हैं। देश की 140 करोड़ जनता देख रही है, उसे मालूम है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने विदेशों में अराजकता फैलाई। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि सत्ता बदल देंगे।

उत्तरकाशी के केदारताल में फंसे 8 लोगों की तलाश जारी

हेलीकॉप्टर से दो बार हवाई सर्वे,अब तक नहीं मिला सुराग

देहरादून/उत्तरकाशी (एजेंसी)। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र के केदारताल ट्रेक पर हिमस्खलन के बाद फंसे सात ट्रेकर्स और एक गाइड की तलाश जारी है। रविवार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्षेत्र की दो बार हवाई रेकी की गई, लेकिन लापता लोगों या उनके टेंट का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। अत्यधिक बर्फबारी और दुर्गम परिस्थितियों के कारण रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। अभियान के लिए एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त माउंटेनियरिंग टीम को जरूरी उपकरणों के साथ रवाना किया गया है। केदारताल क्षेत्र में फंसे आठ लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से दो बार हवाई सर्वे किया गया। हालांकि, इस दौरान लापता ट्रेकर्स या उनके टेंट की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।



अधिकारियों के अनुसार, इलाके में जगह-जगह हिमस्खलन होने के कारण पैदल रेस्क्यू करना मुश्किल है। ऐसे में हेली रेस्क्यू के जरिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया कि प्रतिकूल मौसम के चलते शनिवार को गंगोत्री लौट आई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र की टीमों को पैदल रेस्क्यू के लिए ट्रेक पर नहीं भेजा गया। देहरादून से हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू अभियान के लिए उड़ान भरने की सूचना है।

13 सदस्यीय दल के चार सदस्य सुरक्षित लौटे

जानकारी के अनुसार, बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ट्रेकर्स का 13 सदस्यीय दल गंगोत्री धाम से केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था। दल के साथ गया एक कुक रास्ते से ही गंगोत्री वापस लौट आया था। बाकी सदस्यों की वापसी गुरुवार को होनी थी, लेकिन बाद में सूचना मिली कि हिमस्खलन के कारण दल भोजखड़क के पास फंस गया है। इसके बाद ट्रेकिंग एजेंसी ने दल की तलाश के लिए एक टीम भेजी। इस टीम को चार सदस्य सुरक्षित मिले, जो शनिवार को गंगोत्री लौट आए। शेष आठ लोगों में सात ट्रेकर्स और एक गाइड शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फंसे हुए आठ लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेकी की गई थी। इस दौरान उनके सुरक्षित स्थान पर होने की जानकारी मिली थी। हालांकि, इनमें से एक ट्रेकर के सिर में चोट लगने की सूचना है। अत्यधिक बर्फबारी और दुर्गम रास्तों के चलते रेस्क्यू टीमों को अभियान आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त माउंटेनियरिंग टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ रवाना किया गया है। वहीं, गढ़वाल हिमालय माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेन्द्र राणा ने किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की मांग की है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इजराइल में अरब पार्टियां बनेगी सत्ता की धुरी

यह देश की भावी लोकतांत्रिक दिशा, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, युद्ध नीति और अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है। नेतन्याहू के नेतृत्व को मिली चुनौती इस बात का संकेत है कि लंबे युद्ध, सुरक्षा विफलताओं और राजनीतिक जवाबदेही के सवालों को अनिश्चितकाल तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(लेखक- राज कुमार सिन्हा)

इजराइल के हालिया आम चुनावों के अंतिम नतीजों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें हासिल हुई हैं। विपक्षी गठबंधन के गादी आइजेनकोट के नेतृत्व को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने 19 सीटें हासिल की हैं। सरकार बनाने के लिए संसद में 61 सीटों का बहुमत आवश्यक है। अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की 19 सीटें पिछले चुनावों की तुलना में लगभग दोगुनी है। अरब मतदाताओं ने नेतन्याहू सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में एकजुट होकर मतदान किया, जिससे इजराइल का पारंपरिक दक्षिणपंथी राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों और उसके बाद गाजा, लेबनान तथा ईरान से जुड़े क्षेत्रीय संघर्षों के बाद यह पहला चुनाव था। लंबे समय से चल रहे युद्ध, गहराते अंतरराष्ट्रीय अलगाव और सुरक्षा चूकों को लेकर जनता में उपजी थकान ने नेतन्याहू के खिलाफ माहौल को प्रभावित किया है। नेतन्याहू पर वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। यदि वे सत्ता से बाहर होते हैं या बहुमत जुटाने में नाकाम रहते हैं, तो उनके खिलाफ चल रहे मामलों और 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच का दायरा और कड़ा हो सकता है। नेतन्याहू के 53 सीटों वाले गुट और विपक्ष के 48 सीटों वाले गुट को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 19 सीटों वाली अरब पार्टियां पूरे राजनीतिक गणित में किंगमेकर की भूमिका में आ गई है। हालांकि, यहूदी दक्षिणपंथी दलों और विपक्षी गुट के कुछ सदस्यों के बीच अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन को लेकर तीखा वैचारिक विरोध है, जिससे सरकार बनाना बेहद पेचीदा हो गया है। सरकार गठन के लिए विभिन्न दलों के बीच मोलभाव और हफ्तों या महीनों तक राजनीतिक गतिरोध रहने की आशंका है। विकल्प के तौर पर अल्पमत सरकार बनाने या दलबदल के जरिए सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें की जा सकती है। चुनाव के आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति को सौंपे जाने हैं। यदि कोई औपचारिक गठबंधन नहीं बनता है, तो नेतन्याहू बाहरी समर्थन अथवा कुछ सांसदों के मतदान के दौरान सदन से बाहर रहने के भरोसे एक कमजोर अल्पमत सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि सभी पक्ष कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार बनाने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इजराइल में नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए और अधिक सहयोगियों की तलाश करनी होगी। लेकिन राजनीति और विचारधारा को लेकर गहरे मतभेद गठबंधन समझौते तक पहुंचना आसान नहीं बनाते। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हटाने के लिए विपक्ष का सबसे व्यावहारिक विकल्प इजराइल में अरबों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन बनाना है। लेकिन इसी बीच दो दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है। एक अन्य संभावना यह है कि दोनों मौजूदा राजनीतिक गुटों की पार्टियां आपसी टकराव जारी रखने के बजाय एकजुट होकर एकता सरकार का गठन करें। इस योजना के तहत नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अपने मौजूदा सहयोगियों और कम से कम एक विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जुटाने का प्रयास करेगी। इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि आइजेनकोट ने घोषणा कर दी है कि वह नेतन्याहू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यदि वह अपना रुख बदलते हैं, तो उन्हें उन मतदाताओं का समर्थन खोने का खतरा है जो नेतन्याहू के शासन का अंत चाहते हैं। गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट, एविग्डोर लिबरमैन और यायर गोलान सहित सभी चार विपक्षी दलों के नेताओं ने भी घोषणा की है कि वे नेतन्याहू के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस बीच, नेतन्याहू के गुट को संसद में बहुमत हासिल करने के लिए अभी भी आठ सीटों की कमी है। इसलिए विपक्ष के आठ सांसदों को पाला बदलने के लिए राजी करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। खबर है कि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल 7 सीटों वाली यूनाइटेड तोरा यहूदी (यूटीजे) पार्टी ने गादी आइजेनकोट के विपक्षी गठबंधन को समर्थन देने का और विश्वास मत से गैरहाजिर रहने का प्रस्ताव रखा है। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग संसद में सीटें जीतने वाली पार्टियों के नेताओं के साथ सार्वजनिक परामर्श करेंगे। विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति एक सांसद का चयन करेंगे, जिन्हें नई सरकार बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। चूंकि अरब दलों द्वारा आइजेनकोट का समर्थन किए जाने की संभावना है, इसलिए येशर पार्टी के नेता को यह अवसर सबसे पहले दिया जा सकता है।नियमों के अनुसार, सरकार बनाने के लिए नियुक्त व्यक्ति को 28 दिन का समय मिलेगा और उसे 14 दिनों तक का विस्तार दिया जा सकता है। यदि पहला उम्मीदवार असफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति यह कार्य किसी अन्य सांसद को सौंप सकते हैं। इस व्यक्ति को संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाने के लिए 28 दिन का समय मिलेगा। यदि अन्य सभी विकल्प विफल हो जाते हैं, तो इजराइल को नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इस चुनाव के परिणामों ने इजराइल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। लंबे समय से देश की राजनीति में प्रभावशाली रहे दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समीकरण को पहली बार इतनी गंभीर चुनौती मिली है। अरब पार्टियों की बढ़ी हुई सीटें केवल चुनावी सफलता नहीं हैं, बल्कि यह इजराइल के भीतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों और सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष का भी संकेत देती हैं। आने वाले समय में इजराइल की राजनीति मुख्य रूप से तीन संभावनाओं के इर्द-गिर्द घूम सकती है। पहली संभावना यह है कि विपक्षी दल अरब पार्टियों के समर्थन से नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए साझा मोर्चा बनाएं। ऐसा होने पर इजराइल में पहली बार अरब राजनीतिक दलों की भूमिका सरकार गठन में निर्णायक स्तर तक पहुंच सकती है। इससे देश की राजनीति में यहूदी और अरब नागरिकों के बीच राजनीतिक सहभागिता का नया अध्याय शुरू हो सकता है। दूसरी संभावना एक कमजोर गठबंधन अथवा राष्ट्रीय एकता सरकार की है। यदि नेतन्याहू के विरोधी और कुछ दक्षिणपंथी दल किसी साझा कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, तो सरकार का गठन संभव हो सकता है। लेकिन ऐसी सरकार में विदेश नीति, फिलिस्तीन के सवाल, गाजा युद्ध, सुरक्षा नीति और न्यायिक सुधार जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने रहेंगे। इसलिए उसका स्थायित्व भी एक बड़ी चुनौती होगा। तीसरी संभावना यह है कि कोई भी राजनीतिक गुट बहुमत हासिल नहीं कर पाए और इजराइल को फिर से चुनाव की ओर जाना पड़े। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बार-बार चुनाव होने से न केवल शासन व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि युद्ध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी अनिश्चितता के घेरे में आ सकती है। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू नेतन्याहू का व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य भी है। भ्रष्टाचार के मुकदमे, 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलताओं की जवाबदेही और लंबे युद्ध को लेकर उठ रहे सवाल उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। सत्ता से बाहर होने की स्थिति में उनके खिलाफ जांच और राजनीतिक जवाबदेही की मांग और तेज हो सकती है। दूसरी ओर, यदि वे किसी तरह सत्ता में वापसी करते हैं, तो उन्हें पहले की तुलना में अधिक सीमित राजनीतिक समर्थन के साथ सरकार चलानी पड़ सकती है। इजराइल की भावी राजनीति का प्रभाव केवल देश की आंतरिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। गाजा में युद्ध का भविष्य, फिलिस्तीन के साथ संबंध, लेबनान और ईरान के प्रति नीति तथा अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ संबंध भी नई सरकार की राजनीतिक दिशा से प्रभावित होगी। यदि नई सरकार युद्ध समाप्त करने, कूटनीतिक समाधान और फिलिस्तीन के राजनीतिक अधिकारों पर अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है, तो इजराइल के अंतरराष्ट्रीय अलगाव को कम करने की संभावना बन सकती है। इसके विपरीत, यदि दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी राजनीति का दबदबा बना रहता है, तो क्षेत्रीय तनाव और अंतरराष्ट्रीय आलोचना जारी रहने की आशंका है।इसलिए इजराइल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सरकार गठन का सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। यह देश की भावी लोकतांत्रिक दिशा, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, युद्ध नीति और अरब नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है। नेतन्याहू के नेतृत्व को मिली चुनौती इस बात का संकेत है कि लंबे युद्ध, सुरक्षा विफलताओं और राजनीतिक जवाबदेही के सवालों को अनिश्चितकाल तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।अरब नागरिकों की बढ़ती राजनीतिक भूमिका और युद्ध से थकी जनता का बदलता जनादेश भविष्य में देश की सत्ता संरचना और पश्चिम एशिया की राजनीति दोनों को नई दिशा दे सकता है।

(बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

एक बड़ी सफलता

निश्चित रूप से विश्व बैंक की रिपोर्ट निर्धनता निवारण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करने वाली है, लेकिन सरकार को गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों की कमी, आय में असमानता, युवा बेरोजगारी में वृद्धि और श्रम उत्पादकता में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा

विश्व बैंक की निर्धनता एवं समानता संबंधी रिपोर्ट का यह तथ्य भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का सूचक है कि 2011 से 2023 के बीच देश में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। जहां अत्यधिक निर्धन वर्ग के लोगों की संख्या में करीब 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और अब ऐसे लोगों की संख्या मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई है, वहीं निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों की संख्या में भी खासी गिरावट आई है। चूंकि 2011 से 2023 के कालखंड में मोदी सरकार के कार्यकाल की हिस्सेदारी अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से निर्धनता को दूर करने में जो सफलता मिली, उसका श्रेय उसके खाते में कहीं अधिक जाएगा। निर्धनता में कमी का प्रमुख कारण खपत में वृद्धि, रोजगार और विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी के साथ खाद्य सब्सिडी जैसे कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण की कई योजनाएं हैं। वैसे तो गरीबी हटाओ के नाम पर सभी सरकारें निर्धनता दूर करने की योजनाएं चलाती रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को जितने प्रभावी ढंग से मोदी सरकार ने चलाया और उन्हें जमीन पर उतारा, वह एक मिसाल है। मोदी सरकार ने विकास के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में जैसी सफलता हासिल की है, वैसी पिछली सरकारें नहीं कर सकीं। जिन जनकल्याणकारी योजनाओं ने निर्धनता निवारण में विशेष रूप से योगदान दिया, उनमें जन-धन, आवास, शौचालय, बिजली, हर घर को नल से जल जैसी योजनाएं तो शामिल हैं ही, इसके अतिरिक्त मुद्रा एवं आयुष्मान योजना ने भी निर्धनता निवारण में एक बड़ी भूमिका निभाई। इसी तरह मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम ने भी निर्धन लोगों को बड़ा सहारा दिया। जहां कुछ जनकल्याणकारी योजनाओं ने निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया, वहीं कुछ ने उन्हें अपनी आय बढ़ाने के अवसर भी प्रदान किए। ऐसे अवसर विकास की योजनाओं और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण संबंधी योजनाओं ने भी उपलब्ध कराए। निर्धनता में लगातार कमी आने के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था का पिछले अनेक वर्षों से सबसे तेज गति से बढ़ना भी रहा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत गरीबी से लड़ने में इसके बावजूद सक्षम रहा कि उसे कोविड महामारी का भी सामना करना पड़ा। वैसे तो इस महामारी का सामना पूरे विश्व ने किया, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। निश्चित रूप से विश्व बैंक की रिपोर्ट निर्धनता निवारण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करने वाली है, लेकिन सरकार को गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसरों की कमी, आय में असमानता, युवा बेरोजगारी में वृद्धि और श्रम उत्पादकता में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा।

सरपंच की प्लेट और लोकतंत्र की .....!



लेखाराम बिश्नोई
लेखक विचारक

सरपंच गांव का मालिक नहीं, बल्कि जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवक है। उसका दायित्व गांव में सामाजिक समरसता बढ़ाना, आपसी विवादों का समाधान करना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। गांव के बच्चे और युवा अपने जनप्रतिनिधियों के व्यवहार से भी सीखते हैं। इसलिए सरपंच का आचरण केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, सामाजिक विषय है। उसे नशामुक्त वातावरण, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक विकास का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ग्राम स्वराज की भावना या पद और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन?

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य गांवों में लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना भी इसी भावना पर आधारित थी कि गांव अपने विकास के निर्णय स्वयं करें और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से हो। सरपंच और पंच केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज के विकास और सामाजिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर यानी ग्राम पंचायतों के चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। सरपंच और पंच दोनों स्तरों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। अब गांवों को अपने नए प्रतिनिधि मिल गए हैं। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और रील समाज की बदलती मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

कहीं विजय के तुरंत बाद गाड़ी पर सरपंच की प्लेट लगवाने की होड़ है, तो कहीं समर्थकों के काफिले के साथ पद का प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए चुनाव जीतना मानो गांव की सेवा का अवसर नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक हैसियत और रुतबा दिखाने का प्रमाणपत्र बन गया है। ऐसा लगता है कि गांव का विकास बाद में होगा, पहले गाड़ी की पहचान बदलना जरूरी है!

पद मिला है या रुतबा दिखाने का लाइसेंस?

विडंबना देखिए कि जिस पद की कल्पना गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए की गई थी, उसे कुछ लोग व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का माध्यम समझने लगे हैं। गाड़ी पर सरपंच लिखवाने की जल्दी है, लेकिन गांव की टूटी सड़कों, पेयजल की समस्या, विद्यालयों की स्थिति और किसानों की परेशानियों पर चर्चा के लिए समय नहीं है।

क्या सरपंच की प्लेट लगते ही गांव का विकास शुरू हो जाएगा? क्या समर्थकों के काफिले से गांव की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? क्या पदनाम का प्रदर्शन जनता के प्रति जवाबदेही का विकल्प बन सकता है?

चिंता का एक और गंभीर पक्ष चुनावी माहौल में बड़े स्तर पर अफीम और शराब के प्रयोग तथा इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है। चुनावी जीत के जश्न में नशे का प्रदर्शन, हुड़दंग और शक्ति प्रदर्शन आखिर समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? जिस नेतृत्व से युवा पीढ़ी को संयम, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक आचरण की प्रेरणा मिलनी चाहिए, यदि वही नशे को प्रतिष्ठा का विषय बनाएगा तो सामाजिक आदर्शों की स्थिति क्या होगी?

मतदाता भी करें आत्ममंथन

सवाल केवल प्रत्याशियों से नहीं, मतदाताओं से भी है। हम किस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं? उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रभाव, जातीय पहचान और चुनावी खर्च देखकर या उसके चरित्र, व्यवहार और गांव के विकास की दृष्टि देखकर?

यदि चुनाव में धनबल, नशा, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव योग्य नेतृत्व से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएं, तो चुनाव परिणामों से विकास की अपेक्षा करना अपने आप में विरोधाभास है। लोकतंत्र में मतदाता की जिम्मेदारी मतदान करने तक सीमित नहीं है। उसे अपने प्रतिनिधि के कार्यों पर नजर रखनी चाहिए और ग्रामसभा में सक्रिय सहभागिता निभानी चाहिए।

गांव का नेतृत्व समाज का आदर्श बने

सरपंच गांव का मालिक नहीं, बल्कि जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि और सेवक है। उसका दायित्व गांव में सामाजिक समरसता बढ़ाना, आपसी विवादों का समाधान करना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। गांव के बच्चे और युवा अपने जनप्रतिनिधियों के व्यवहार से भी सीखते हैं। इसलिए सरपंच का आचरण केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, सामाजिक विषय है। उसे नशामुक्त वातावरण, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक विकास का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

पांच वर्ष बाद जनता गाड़ी पर लगी प्लेट नहीं देखेगी, बल्कि यह पूछेगी कि कितनी सड़कें बनीं, पेयजल की समस्या कितनी दूर हुई, कितने जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिला और ग्रामसभा में कितनी पारदर्शिता रही।

सवाल केवल सरपंच की प्लेट का नहीं, हमारी सामाजिक सोच का है। पंचायत चुनाव गांव के भविष्य और सामाजिक नेतृत्व की दिशा तय करने का अवसर हैं। सरपंच की प्लेट कुछ मिनटों में लग जाती है, लेकिन जनता का विश्वास अर्जित करने में पूरा कार्यकाल लग जाता है। लोकतंत्र में पद से बड़ा दायित्व और रुतबे से बड़ा जनविश्वास होता है। सरपंच की वास्तविक पहचान उसकी गाड़ी पर लिखे पदनाम से नहीं, बल्कि गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आई संतुष्टि से होनी चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था तभी सार्थक होगी, जब पद प्रदर्शन का नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का माध्यम बनेगा।

लेखाराम बिश्नोई
लेखक व विचारक

विश्वास की ताकत



एक अंग्रेज अफसर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ जहाज में सवार होकर सफर पर निकला। रास्ते में समुद्र में जोर का तूफान आया। मुसाफिर घबरा उठे। पर वह अंग्रेज अफसर जरा भी नहीं घबराया। उसकी पत्नी भी व्याकुल हो गई थी। उसने अपने पति से पूछा-इतना खतरनाक तूफान आया है। सबकी हालत खराब है। पर आप इतना निश्चिंत कैसे बैठे हैं?

यह सुनते ही उस अफसर ने म्यान से तलवार निकाली और पत्नी के सिर पर रखकर पूछा- क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी बोली-मेरी बात का जवाब न देकर आप यह क्या खेल कर रहे हैं? अफसर ने फिर पूछा-बताओ, तुम्हें डर लग रहा है या नहीं? पत्नी ने कहा- मुझे भला क्यों डर लगेगा? मुझे पता है आप मेरी जान नहीं लेंगे क्योंकि आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। फिर मैं क्यों डरूं?

इस पर अफसर ने कहा-बिल्कुल सही। जिस तरह तुम्हें मुझ पर भरोसा है उसी तरह मुझे ईश्वर पर भरोसा है। वह हम सब का अभिभावक है। वह हमारा बुरा क्यों चाहेगा? वह तो हमारे पिता के समान है। वह हर संकट में हमारी सहायता ही करेगा। इसलिए तूफान आया है तो वह चला भी जाएगा। जीवन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इससे हमें बड़ी ताकत मिलती है। हम इसी ताकत के सहारे जीते हैं। इसलिए हमें किसी न किसी के प्रति विश्वास तो रखना ही होगा। वही लोग घबराते हैं या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं जिनमें विश्वास की कमी होती है। संयोग से उसी समय तूफान थम गया।

सुप्रीम कोर्ट सरकार के निर्णयों को नीतिगत मामला बताकर समीक्षा- निर्णय से क्यों बच रही?

(लेखक- सनत जैन)

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं। संसद और विधानसभाएं कानून बनाती हैं, सरकारें उनके क्रियान्वयन के लिए नियम और प्रशासनिक आदेश जारी करती हैं। जबकि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है, इन कानूनों और आदेशों से संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। ऐसे में सवाल उठता है, जब सरकार के किसी निर्णय को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो उसे नीतिगत मामला बताकर न्यायिक समीक्षा से दूरी क्यों बनाई जाती है? क्या यह न्यायपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटने की प्रवृत्ति है, या इसके पीछे कोई अन्य कारण है? भारतीय संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों और अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सरकार को नीतियां बनाने का अधिकार है, कोई भी नीति संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून, उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और प्रशासनिक आदेश-सभी संवैधानिक कसौटी पर परखने, समीक्षा करने के बाद निर्णय देने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। नियमों को सामान्यतः विधायिका में कानूनों की तरह पारित नहीं किया जाता है। उनकी वैधानिकता और संवैधानिकता की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। यही न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हाल ही में जनगणना 2027 के डिजिटल फॉर्म में ओबीसी जातियों की जानकारी दर्ज करने के विकल्प को लेकर विवाद सामने आया। ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मांग की थी, ड्रॉपडाउन सूची में ऐसा विकल्प उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोग अपनी जाति और समुदाय के अनुसार जानकारी दर्ज कर सकें। पिछली जनगणना में यह विकल्प था। संगठन का कहना था, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के समक्ष मांग रखने के बाद भी राहत नहीं मिली। इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका पर सुनवाई के बाद संबंधित मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग रखने का निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया। इससे यह प्रश्न उठता है, जब संबंधित विभाग के समक्ष पहले ही मांग रखी जा चुकी हो, तब याचिकाकर्ता को दोबारा उसी प्रक्रिया में भेजने से उसे राहत कैसे मिलेगी?

यह अकेला मामला नहीं है। चुनाव आयोग की नियुक्ति से संबंधित कानून, चुनावी पारदर्शिता और अन्य संवैधानिक प्रश्नों पर लंबित याचिकाओं को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों की अपेक्षा है, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अदालतें समयबद्ध सुनवाई के साथ तारीख पर तारीख अथवा सुझाव देने के स्थान पर स्पष्ट निर्णय दें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा विपक्ष की चिंताएं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का प्रयास और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह भी इसी व्यापक बहस का हिस्सा है। यह कहना उचित नहीं होगा, हर मामले में न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है। किसी याचिका को खारिज करने, वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश देने या अंतरिम राहत से इनकार करने के पीछे कानूनी कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जब संवैधानिक महत्व के मामलों में लंबे समय तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब न्यायिक निष्क्रियता की धारणा मजबूत होने लगती है।

अदालतों की स्वतंत्रता के साथ-साथ उनकी निष्पक्षता और समयबद्ध न्याय भी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों द्वारा कोर्ट रूम में तोड़फोड़ की घटना ने न्यायपालिका और वकीलों के बीच बढ़ते तनाव पर भी चिंता पैदा की है। असहमति और आक्रोश व्यक्त करने के लोकतांत्रिक तरीके हो सकते हैं। अदालत में हिंसा या तोड़-फोड़ किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती है। दूसरी ओर, न्याय व्यवस्था को भी यह समझना होगा, न्याय में अनावश्यक देरी और निर्णयों के अभाव से असंतोष बढ़ रहा है। अब समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जनहित, मौलिक अधिकारों, चुनावी प्रक्रिया और व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करें। न्यायपालिका को केवल सरकार के निर्णयों पर मुहर लगाने वाली संस्था नहीं, बल्कि संविधान की संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी। लोकतंत्र में न्यायपालिका पर जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। नागरिकों को समय पर न्याय और स्पष्ट निर्णय नहीं मिलेंगे, तो न्यायपालिका और न्यायाधीशों के प्रति विश्वास कमजोर होगा। सरकार के दबाव में काम करने की धारणा को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है- स्वतंत्र, पारदर्शी, तर्कसंगत और समयबद्ध न्याय लोगों को मिले। जिस तरह से आर्थिक मंदी बेरोजगारी, टैक्स, कर्ज, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मामलों को लेकर दिन-प्रतिदिन जन असंतोष बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की सक्रियता बहुत जरूरी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

चीनी के दाम एक सप्ताह में 62 रुपए बढ़े

चावल, गेहूं, अधिकतर दालें और खाद्य तेल भी हुए महंगे

नई दिल्ली ।

बीते सप्ताह घरेलू थोक जिंस बाजारों में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। चीनी, चावल, गेहूं, दालों और खाद्य तेलों सहित अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। चीनी लगातार चौथे सप्ताह महंगी हुई है, जिसके खुदरा बाजार में भी दाम बढ़े हैं। थोक बाजारों में बीते सप्ताह चीनी औसतन 62 रुपये प्रति क्विंटल महंगी होकर 5,506 रुपये पर पहुंच गई, जबकि खुदरा बाजार में यह 58 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़कर 59.18 रुपये हो गई। हालांकि, गुड़ के भाव में 3 रुपये की नरमी रही। अनाज खंड में भी तेजी देखने को मिली। चावल की औसत कीमत 70 रुपये बढ़कर 4,377 रुपये प्रति क्विंटल हो गई, वहीं गेहूं 29 रुपये महंगा होकर 2,939 रुपये और आटा 18 रुपये बढ़कर 3,395 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। दालों में भी उछाल रहा; तुअर दाल 162 रुपये, चना दाल 69 रुपये, मूंग दाल 34 रुपये और उड़द दाल 31 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। इसके विपरीत, मसूर दाल 33 रुपये सस्ती हुई। खाद्य तेलों में भी कीमतें बढ़ीं। सरसों तेल सर्वाधिक 233 रुपये, पाम ऑयल 51 रुपये, सूरजमुखी तेल 39 रुपये, सोया तेल 12 रुपये और मूंगफली तेल 11 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। हालांकि, वनस्पति तेल में 52 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई।

1 दिन में 28.6 फीसदी टूटा, इंटेल का शेयर, एआई खर्च पर निवेशकों ने उठाए सवाल

न्यूयॉर्क।

अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी इंटेल के शेयर एक ही दिन में 28.6 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है । इस गिरावट ने वैश्विक शेयर बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में आगे निकलने के लिए इंटेल बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। कंपनी के डेटा सेंटर, चिप निर्माण और एआई तकनीक से जुड़े खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। निवेशकों को इन भारी खर्चों के मुकाबले मुनाफे और भविष्य की कमाई पर कोई बेहतर भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। निवेशक कंपनी के प्रबंधन से सवाल कर रहे हैं। एआई पर लगाए जा रहे अरबों डॉलर का वास्तविक आर्थिक लाभ निवेशकों को कब मिलेगा। इसको लेकर निवेशक आशंकित हैं।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की बिक्री 19 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली ।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की अक्टूबर, 2026 में थोक बिक्री सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 8,013 वाहन पर पहुंच गई।कंपनी के अनुसार, हाल ही में पेश किए गए मॉडल एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी और विंडसर इंडल्ज एडिशन को ग्राहकों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। देशभर में इन मॉडल की डिलिवरी में भी तेजी देखने को मिल रही है।जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, जेएसडब्ल्यू समूह और चीन की एसएआईसी मोटर का संयुक्त उद्यम है।

हुंदै की बिक्री 17.7 प्रतिशत बढ़कर 82,299 इकाई पर

नई दिल्ली ।

हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने अक्टूबर में अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने बीते माह घरेलू बाजार और निर्यात मिलाकर कुल 82,299 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.7 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी ने रविवार को जारी बयान में बताया कि अक्टूबर में उसकी घरेलू बिक्री 16.7 प्रतिशत बढ़कर 62,799 इकाई रही। वहीं निर्यात में 21.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 19,500 इकाई पर पहुंच गया। हुंदै मोटर इंडिया के अधिकारी ने कहा कि त्योहारी मांग में मजबूती और घरेलू एवं निर्यात बाजारों में बेहतर प्रदर्शन के चलते कंपनी ने बिक्री का नया रिकॉर्ड हासिल किया है। खबरों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में देश में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 29.7 प्रतिशत बढ़कर 26.59 लाख इकाई तक पहुंच गई। वहीं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रों का बाजार वर्ष 2025 के 6,139 करोड़ रुपये से बढ़कर 2030 तक 21,940 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

तिमाही नतीजे,आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे नई दिशा

निवेशकों की नजर अब ऑटो बिक्री, पीएमआई और दिग्गज कंपनियों के आय पर

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद अब निवेशकों की निगाहें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों के तिमाही नतीजों और वैश्विक घटनाक्रमों पर टिकी रहेंगी। ये सभी कारक बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आने वाले हफ्ते में ऑटो कंपनियों के अक्टूबर महीने के बिक्री आंकड़े और मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज पीएमआई रिपोर्ट्स जारी होंगी। इसके साथ ही आईटीसी, मैरिको, पेट्रोनेट एलएनजी, अपोलो हॉस्पिटल्स, बीएसई, डाबर, एलआईसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंडाल्को जैसी नौ दिग्गज कंपनियां अपने दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित करेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में मिडटर्म चुनाव, रोजगार के आंकड़े और एप्पल व एएमडी जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे भी बाजार को प्रभावित करेंगे। बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी करते हुए जबरदस्त बढ़त दर्ज की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने, कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और फार्मा व आईटी शेयरों में आई मजबूत खरीदारी ने बाजार के उत्साह को बढ़ाया। सेक्टरवार प्रदर्शन में फार्मा और हेल्थकेयर में 7 फीसदी तक की जोरदार तेजी देखने को मिली, जबकि मीडिया, कैपिटल मार्केट्स और रियल्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

संस्थागत निवेशकों के मोर्चे पर, अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने 45,161 करोड़ रुपये के शेयरों की भारी बिकवाली की। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 62,220 करोड़ रुपये की मजबूत खरीदारी कर बाजार को सहारा दिया, जिससे एफआईआई की बिकवाली का असर काफी हद तक संतुलित रहा। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व का तनाव चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका सीधा असर भारत के आयात बिल और महंगाई पर पड़ सकता है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक और एसएंडपी में आई गिरावट भी अगले हफ्ते घरेलू बाजार पर दबाव डाल सकती है।

तकनीकी स्तर पर, निफ्टी के लिए 23,150 से 23,160 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसके पार जाने पर 23,500 तक की तेजी संभव है, जबकि नीचे 22,845 अहम सपोर्ट रहेगा। निवेशकों को आगामी हफ्तों में घोषित होने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर पैनी नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

धनतेरस और दीपावली पर खरीदारों की बल्ले-बल्ले

मुंबई ।



धनतेरस और दीपावली से पहले भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण कीमती धातुओं के भाव नीचे आए हैं। 31 अक्टूबर को दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 3,200 रुपये गिरकर 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,200 रुपये टूटकर 1.86 लाख रुपये प्रति किलो रह गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 30 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का बंद भाव 1,40,054 रुपये और चांदी का भाव 1,81,344 रुपये प्रति किलो था। कीमतों में गिरावट से त्योहारों पर आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत मिली है। ज्वेलरी कारोबारियों को भी उम्मीद है कि कम कीमतों के चलते धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी बढ़ेगी। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

महिंद्रा की बिक्री नौ प्रतिशत बढ़कर 1,31,109 इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर

कंपनी का निर्यात 77 प्रतिशत बढ़कर 7,102 इकाई रहा

नई दिल्ली ।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की कुल वाहन बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 1,31,109 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक अक्टूबर में निर्यात सहित कुल बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान निर्यात 77 प्रतिशत बढ़कर 7,102 इकाई रहा। घरेलू यात्री वाहन बिक्री दो प्रतिशत बढ़कर 73,338 इकाई हो गई, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33,037 इकाई रही। कंपनी के एक अे धिकारी ने कहा` कि अक्टूबर में कंपनी की एसयूवी बिक्री 73,338 इकाई और कुल वाहन बिक्री 1,31,109 इकाई रही, जो किसी भी महीने में अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम और नए सिरे से पेश किए गए उत्पादों की वजह से एसयूवी, पिकअप और तिपहिया वाहनों की मांग मजबूत बनी रही। कंपनी के पहले सीएनजी वाहन एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी को भी ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहन सहित तिपहिया वाहनों की बिक्री 38 प्रतिशत बढ़कर 17,632 इकाई हो गई। वहीं, दो से 3.5 टन क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) की बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 28,654 इकाई रही। हालांकि, दो टन से कम क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री चार प्रतिशत घटकर 4,383 इकाई रह गई।

भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई ने अक्टूबर में निकाले 34,843 करोड़

इस साल अब तक कुल निकासी 2.95 लाख करोड़ पहुंची

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निकासी का सिलसिला अक्टूबर महीने में भी जारी रहा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयरों से 34,843 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की है, जो लगातार दूसरा महीना है जब उन्होंने बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाला है। हालांकि, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने फिर से खरीदारी की, जिससे निकट अवधि में निवेश धारणा में सुधार के संकेत मिले हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 34,843 करोड़ रुपये की निकासी से पहले, सितंबर में भी एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 35,861 करोड़ रुपये निकाले थे। इस भारी बिकवाली के बाद, इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की कुल निकासी बढ़कर 2.95 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इससे पहले जुलाई और अगस्त में उन्होंने क्रमशः 20,200 करोड़ रुपये और 29,631 करोड़ रुपये का निवेश किया था। बिकवाली के कारण और वापसी के संकेत- बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अक्टूबर के दौरान विदेशी निवेशकों की बिकवाली के प्रमुख कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों को लेकर चिंता और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल का आकर्षक होना रहे। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत में महंगाई बढ़ाने के साथ कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव डाल सकती हैं, जिससे निवेशकों का रुझान प्रभावित हुआ। हालांकि, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह (26 से 30 अक्टूबर) के दौरान विदेशी निवेशकों ने लगभग 6,300 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया, जो एक सकारात्मक बदलाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला, भारत की बड़ी कंपनियों के शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन और घरेलू अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि के संकेत इस वापसी के संभावित कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केवल एक सप्ताह की खरीदारी को विदेशी पूंजी की वापसी का स्थायी संकेत नहीं माना जा सकता। विदेशी निवेशकों की खरीदारी आगे भी जारी रहेगी या नहीं, यह काफी हद तक वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, कच्चे तेल की कीमतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं भी इस तेजी की गति को सीमित कर सकती हैं।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी बढ़कर 370 रुपए होने का अनुमान

नई दिल्ली ।

दिसंबर 2026 तक 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी बढ़कर लगभग 370 रुपये होने का अनुमान है। अंडर-रिकवरी का मतलब गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत और उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने के बावजूद घरेलू सिलेंडर निर्धारित कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। जानकारों के अनुसार नवंबर 2026 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी लगभग 309 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि दिसंबर में यह बढ़कर 370 रुपये तक पहुंच सकती है। सितंबर में यह अंतर लगभग 184 रुपये प्रति सिलेंडर था, जो अक्टूबर में बढ़कर 229 रुपये हो गया। लगातार बढ़ते अंतर से तेल विपणन कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार में सऊदी अनुबंध मूल्य बढ़कर 756 डॉलर प्रति टन पहुंचने से घरेलू गैस की लागत में भी इजाफा हुआ है। सिलेंडर की खरीद, परिवहन, वितरण और अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद कंपनियों की वास्तविक लागत घरेलू बाजार में तय बिक्री मूल्य से अधिक हो रही है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 942 रुपये होने के बावजूद कंपनियों को अनुमानित 370 रुपये प्रति सिलेंडर का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भारत की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इस अंतर का सामना कर रही हैं। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी हजारों करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी दर्ज की है।

ऐसी स्थिति में कंपनियां सरकारी वित्तीय सहायता की उम्मीद करती हैं। मुआवजा मिलने तक नुकसान की भरपाई के लिए दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्रॉस-सब्सिडी कहा जाता है। याकि` कि कमर्शियल एलपीजी, विमान ईंधन या अन्य कारोबार से होने वाले लाभ के जरिए घरेलू गैस की बिक्री से हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाती है।

अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 2.31 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली ।

देश का कुल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करते हुए 2.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। सरकार द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार घरेलू गतिविधियों में मजबूती और आयात से प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि इस उछाल के प्रमुख कारण रहे। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में घरेलू बिक्री से जीएसटी संग्रह 16 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, वहीं आयात से प्राप्त राजस्व में 42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 72,246 करोड़ रुपये हो गया। कुल जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) का योगदान 42,935 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) का 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी का योगदान 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। रिफंड के समायोजन के बाद, अक्टूबर में शुद्ध जीएसटी संग्रह 26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक सकल जीएसटी संग्रह 13.2 प्रतिशत बढ़कर 14.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो इस सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लोढ़ा डेवलपर्स गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स में कार्यालय परिसर बनाएगी

1,200 करोड़ करेगी निवेश, मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी की यह एनसीआर में पहली परियोजना होगी

नई दिल्ली ।

रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स ने दिल्ली-एनसीआर के संपत्ति बाजार में कदम रखते हुए गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर करीब 1,200 करोड़ रुपये के निवेश से प्रीमियम कार्यालय परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी की यह एनसीआर में पहली परियोजना होगी। पिछले साल लोढ़ा डेवलपर्स ने गुरुग्राम में दो परियोजनाओं के लिए एमआरजी समूह के साथ संयुक्त विकास करार किया था। इनमें से एक परियोजना वाणिज्यिक और एक आवासीय है। लोढ़ा डेवलपर्स के एक अे धिकारी ने बताया कि कंपनी ने हाल में 1.2 एकड़ में फैली अपनी वाणिज्यिक परियोजना लोढ़ा पैंथियन पेश की है। इसमें 27 मंजिलों में कुल चार लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्र होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,100 से 1,200 करोड़ रुपये है। कंपनी इस ग्रेड ए प्लस प्लस वाणिज्यिक परियोजना में कार्यालय स्थल बेचेगी।मोदी के मुताबिक, गुरुग्राम में प्रीमियम कार्यालय स्थल की अच्छी मांग है। कई कारोबारी समूह लंबे समय तक किराये पर कार्यालय लेने के बजाय खुद की व्यावसायिक संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।

कंपनी चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में गुरुग्राम के सोहना रोड पर आवासीय परियोजना भी पेश करने की तैयारी कर रही है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को दी 1.09 लाख करोड़ की सौगात

यूपी को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की है। यह राशि राज्यों को मिलने वाली नियमित मासिक कर हिस्सेदारी के अतिरिक्त है। इससे राज्यों को त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले खर्च के साथ विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्यों को यह अग्रिम किस्त 31 अक्टूबर की रात जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाना है। इससे राज्य सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों के वेतन और अन्य जरूरी भुगतान करने में भी मदद मिलेगी। इस विशेष किस्त में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं सबसे कम 365 करोड़ रुपये सिक्किम को आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय करों से होने वाली कमाई का निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है। इसमें जीएसटी, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स से प्राप्त राजस्व शामिल है। वर्तमान व्यवस्था के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के बीच बांटा जाता है। यह राशि सामान्य रूप से हर महीने किस्तों में जारी होती है। हालांकि, इस बार त्योहारों और बढ़ते सरकारी खर्च को देखते हुए केंद्र ने नियमित किस्त से पहले अतिरिक्त राशि जारी की है। राज्यों को होंगे ये प्रमुख फायदे

- विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट मिलेगा।

- सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम तेज होंगे।

जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जरूरी भुगतान में सुविधा होगी।

- त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले खर्च का प्रबंधन आसान होगा।

तमिलनाडु में शराब की हर बोतल पर 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क

खाली बोतल लौटाने पर मिलेगा पैसा वापस

चेन्नई ।



तमिलनाडु में शराब खरीदने वालों की जेब पर 1 नवंबर से अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। राज्य में अब इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल), बीयर और वाइन की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि, ग्राहकों को राहत देने के लिए खाली बोतल निर्धारित दुकानों पर लौटाने पर यह रकम वापस पाने का विकल्प भी दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री पर पर्यावरण और सामाजिक कल्याण शुल्क लागू किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए धन जुटाना है। इसके साथ ही शराब की खाली बोतलों के उचित निपटान और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय उत्पादकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बोतलों पर नई कीमतों के अनुरूप क्यूआर कोड वाले मूल्य लेबल लगाने होंगे। शराब की दुकानों और लाइसेंस प्राप्त बिक्री केंद्रों पर भी नई व्यवस्था के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, निर्धारित दुकानों और बिक्री केंद्रों पर खाली बोतल लौटाने पर 10 रुपये वापस मिलेंगे, बोतल वापसी के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होगा, खाली बोतलों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने से रोकने में मदद मिलेगी और बोतलों के पुनः उपयोग और उचित निपटान को बढ़ावा मिलेगा।

नई व्यवस्था में शुल्क से जुड़ी वित्तीय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पांच क्षेत्रीय क्षेत्रों में अलग-अलग बैंक खाते बनाए गए हैं। साथ ही दुकानदारों को निर्धारित शुल्क के अलावा मनमानी वसूली नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में सीएनजी महंगी, लखनऊ से उन्नाव तक नई दरें लागू

लखनऊ ।

बढ़ती लागत और वैश्विक आपूर्ति संकट के बीच ग्रीन गैस लिमिटेड ने एक नवंबर से उत्तर प्रदेश में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई है। अलग-अलग शहरों में कीमतों में एक रुपये से लेकर 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे वाहन चालकों के ईंधन खर्च में इजाफा होगा। नई दरों के अनुसार, राजधानी लखनऊ में सीएनजी की कीमत 107 रुपये से बढ़कर 108 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आगरा में भी एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। अयोध्या और सुल्तानपुर में सीएनजी एक रुपये महंगी हुई है। इन दोनों शहरों में अब एक किलोग्राम सीएनजी की कीमत 106 रुपये हो गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उन्नाव में की गई है। यहां सीएनजी की कीमत में 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। नई दर लागू होने के बाद उन्नाव में एक किलोग्राम सीएनजी अब 106 रुपये में मिलेगी। कीमतों में बदलाव से निजी वाहन चालकों के साथ-साथ सीएनजी से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों का खर्च भी बढ़ सकता है। ग्रीन गैस लिमिटेड का कहना है कि वैश्विक स्तर पर गैस की आपूर्ति में संकट और लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में संशोधन किया गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



ब्रजभूमि

भगवान श्रीकृष्ण धन्य हैं, उनकी लीलाएं धन्य हैं और इसी प्रकार वह भूमि भी धन्य है, जहां वह त्रिभुवनपति मानस रूप में अवतरित हुए और ब्रजभूमि जहां उन्होंने वे परम पुनीत अनुपम अलौकिक लीलाएं कीं।

जहां कृष्ण ने की अनेक लीलाएं..

हिंदुस्थान में अनेक तीर्थ स्थान हैं, सबका महात्म्य है, भगवान के और-और भी जन्मस्थान हैं पर यहां की बात ही कुछ निराली है। यहां के नगर-ग्राम, मठ-मंदिर, वन-उपवन, लता-कुंज आदि की अनुपम शोभा भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से देखने को मिलती है।

अपनी जन्मभूमि से सभी को प्रेम होता है फिर वह चाहे खुला खंडहर हो और चाह सुरम्य स्थान, वह जन्मस्थान है, यह विचार ही उसके प्रति होने के लिए पर्याप्त है। इसी से सब प्रकार से सुंदर द्वारका में वास करते हुए भी भगवान श्रीकृष्ण जब ब्रज का स्मरण करते थे, तब उनकी कुछ विचित्र ही दशा हो जाती थी।

जब ब्रज भूमि के वियोग से स्वयं ब्रज के अधीश्वर भगवान श्रीकृष्ण का ही यह हाल हो जाता है, तब फिर उस पुण्यभूमि की रही-सही नैसर्गिक छटा के दर्शन के लिए, उस छटा के लिए जिसकी एक झांकी उस पुनीत युग का, उस जगद् गुरु का, उसकी लौकिक रूप में की गई अलौकिक लीलाओं का अद्भुत प्रकार से स्मरण कराती, अनुभव का आनंद देती और मलिन मन-मंदिर को सर्वथा स्वच्छ करने में सहायता प्रदान करती है, भावुक भक्त तरसा करते हैं।

इसमें आश्चर्य ही क्या है? नैसर्गिक शोभा न भी होती, प्राचीन लीलाचिह्न भी न मिलते होते तो भी केवल साक्षात् परब्रह्म का यहां विग्रह होने के नाते ही यह स्थान आज हमारे लिए तीर्थ था, यह भूमि हमारे लिए तीर्थ थी, जहां की पावन रज को ब्रह्मज्ञ उद्धव ने अपने मस्तक पर धारण किया था।

वह ब्रजवासी भी दर्शनीय थे, जिनके पूर्वजों के भाग्य की साराहना करते-करते भक्त सूरदास के शब्दों में बड़े-बड़े देवता आकर उनकी जूठन खाते थे, क्योंकि उनके बीच में भगवान अवतरित हुए थे।

ब्रज-वासी-पटतर कोउ नाहिं।
ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत, इनकी जूठनि लै लै खाहिं॥
हलधर कह्यौ, छाक जेंवत संग, मीठो लगत सराहत जाहिं।
सूरदास प्रभु जो विश्वम्भर, सो ग्वालनके कौर अघाहिं॥

तब फिर यहां तो अनन्त दर्शनीय स्थान हैं, अनन्त सुंदर मठ-मंदिर, वन-उपवन, सर-सरोवर हैं, जो अपनी शोभा के लिए दर्शनीय हैं और पावनता के लिए भी दर्शनीय हैं। सबके साथ अपना-अपना इतिहास है। यद्यपि मुसलमानों के आक्रमण पर आक्रमण होने से ब्रज की सम्पदा नष्टप्राय हो गई है। कई प्रसिद्ध स्थानों का चिह्न तक मिट गया है, मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी हैं, तथापि धर्मप्राण जनों की चेष्टा से कुछ स्थानों की रक्षा तथा जीर्णोद्धार होने से वहां की जो आज शोभा है, वह भी दर्शनीय ही है।

कैलाश परिक्रमा से मिट जाते हैं जन्मों के कष्ट

तिब्बत स्थित कैलास पर्वत को शास्त्रों में कैलास को मेरू गण पर्वत, रजतगिरि आद नामा से भी वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं कैलास पर्वत शिव आराधना का सर्वोच्च स्थल भी माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार यह भगवान आशुतोष व पार्वती का स्थायी निवास है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव व पार्वती के नृत्य करने से इसका नाम कैलास हुआ। उपासकों का मत है कि स्वयं भू कैलास पर भगवान शंकर का विशाल राजप्रसाद है। जहां केवल ब्रह्म, विष्णु एवं महेश आदि देवों का ही प्रवेश संभव है। कैलास न केवल सनातनधर्मियों बल्कि जैन, बौद्ध व तिब्बितयों के लिए प्रारंभ से ही श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।

यहां विराट एवं अतिभव्य लिग शदल कमल के मध्य में अवस्थित है। इस पवित्र लिग पर सदैव लिपुंड की रचना प्रकृति के पावन करों से होती है। तिब्बती भाषा में कैलास को पवित्र हिम से जाना जाता है। यही कारण है कि तिब्बती कैलास परिक्रमा दंडवत लेट-लेट कर पूर्ण करते हैं। कैलास परिक्रमा मार्ग दरचन से प्रारंभ होता है जो लगभग 54 किलोमीटर का है। मार्ग के क्रम में न्याडीगुम्का, दिराफुक, दोल्माघाटी, गौरीकुंड व जुन्धुलुफुक आदि मनोहारी व रमणीक स्थल पड़ते हैं। इनमें समुद्र तल से 18600 फीट की ऊंचाई पर स्थित दोल्माघाटी कैलास परिक्रमा का सर्वोच्च उच्च स्थल है। 14600 फीट की ऊंचाई पर कैलास से 20 मील पूर्व ही दो पवित्र सरोवर राक्षसताल व मानसरोवर बरबस ही उपासकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राक्षसताल के संबंध में वर्णित है कि इसी स्थल पर लंकापति रावण ने खड़े होकर भगवान आशुतोष की अर्चना की थी जबकि मानसरोवर में भगवती सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। ऐसा मत है कि यहां की शक्ति दाक्षयाणी व भैरव अमर हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसरोवर के पवित्र जल में तैरते हुए राजहंस व उत्ताल तरंगों की सुमधुर ध्वनि शैल शिखरों से प्रतिध्वनित होकर उत्पन्न नैसर्गिक संगीत का खुशनुमा वातावरण उपासकों को प्रकृति व अध्यात्म के समीप खींच लाती है जिससे उपासक को अलौकिक शांति का अनुभव होता है। जैन ग्रंथों में जहां मानसरोवर को पद्मपद से वर्णित किया गया है। मानसरोवर के पश्चिम में स्थित राक्षसताल की छटा ही निराली है। मानसरोवर स्थित मां शक्ति की प्रतिमा पाषाण रूप में है। जहां मां भगवती की अर्चना होती है। विभिन्न साहित्यकारों व कवियों ने अपने साहित्य में मानसरोवर की महत्ता का सुंदरतम वर्णन किया है जिनमें कवि कालिदास के मेघदूत आदि ग्रंथ मुख्य हैं। कैलास के अप्रतिम सौंदर्य व भगवान शंकर के सर्वोच्च उपासना स्थल होने के कारण उपासक प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कैलास परिक्रमा हेतु जाते हैं। पुराण में वर्णित है कि कैलास की एक प्रक्रिमा से ही जन्म- जन्मांतर के पाप कर्म देर हो जाते हैं।



दांम्पत्य जीवन को बनाएं तनावरहित

आज का यह बदलता परिवेश सिर्फ जीवनशैली में ही प्रभाव नहीं डालता अपितु वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सबब बन रही है। कई दम्पतियों में आपसी सामंजस्य एवं प्रेम का अभाव देखने को मिल ही जाता है। दम्पति में नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में न सिर्फ प्रभावित दम्पति, वरन् पूरा परिवार परेशान हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए ये उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं-

- यदि किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के कारण दाम्पत्य क्लेशपूर्ण बन रहा है, तो 7-7 गोमती चक्र, लघु नारियल एवं लघु शंख लें। इन्हें सवा गज के नए पीले वस्त्र में बांध लें। इसे प्रभावित (पति अथवा पत्नी) पर से सात बार उसार का बहते पानी में बहा दें। बहाने के बाद पीछे मुड़कर देखे बगैर सीधे घर लौट आएं।
- यदि दम्पति अथवा समूचे परिवार में वैचारिक मतभेद रहता है, तो प्रातःकाल उठते ही जिस मटके से परिवार के सभी सदस्य जल पीते हैं, उससे एक लोटा पानी भरें और उसे पूरे घर के प्रत्येक कक्ष में तथा छत पर छिड़कें। इस दौरान किसी से बात नहीं करें, साथ ही मन ही मन ॐ शांति का निरंतर उच्चारण करते रहें।
- परिवार में यदि पति-पत्नी के मध्य क्लेश रहता हो अथवा अन्य पारिवारिक सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद अधिक रहते हों, तो प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जपें-

धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी।
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु॥

- नवरात्र, दीपावली किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी का पौधा लगाएं। उसमें प्रतिदिन सायंकाल घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे परिवार अथवा प्रभावित दम्पति में सुख-शांति कायम रहेगी।

ऐसे लोगों को मिलती है कैरियर में कामयाबी

आज हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए निरंतर प्रयोग करता रहता है। अच्छा कैरियर किसे पसंद नहीं होता। अच्छे कैरियर के लिए युवा तरह-तरह कि जतन किया करते हैं। लेकिन जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है सही कैरियर का चुनाव। क्योंकि अक्सर कैरियर का सही चुनाव नहीं कर पाने के कारण ही व्यक्ति को जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। अंक ज्योतिष में कैरियर के चुनाव के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। इस तरीके को आजमाएं तो आप खुद ही अपने लिए सही कैरियर का चुनाव कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति कहलाएंगे।

अंक ज्योतिष अनुसार हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है। इस अंक को ज्ञात करके व्यक्ति अपने लिए सही कैरियर का चुनाव करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती हैं क्योंकि मूलांक जिस क्षेत्र में कैरियर का संकेत देता है उस क्षेत्र में सफलता के लिए जो गुण चाहिए वह व्यक्ति में मौजूद होता है। जैसे किसी व्यक्ति का मूलांक 1 होता है तो उनमें नेतृत्व की योग्यता होती है। ऐसे व्यक्ति राजनीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। वकालत के अलावा जिन क्षेत्रों में अधिक जोश और उत्साह की जरूरत होती है जैसे सेना, पुलिस के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिल ही जाती है। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाईनर, नाविक, नौसेना, ठेकेदारी, व्यवसाय एवं शिल्पकला के क्षेत्र में भी यह कामयाब होते हैं।

कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए अपनाएं यह उपाय

देश और दुनिया में हो रहे विकास से लोगों विलासिता का सुख भोगने से अपने आप को कभी दुर नहीं रख पाते। इन सुखों के लिए लोग कर्ज लेने से भी पीछे नहीं हटते। जबकि एक तरह से कर्ज मानव जीवन के लिए अभिशाप होता है। जिस व्यक्ति पर कर्ज है वो व्यक्ति जिन्दा रहते हुए भी चलती - फिरती लाश के समान है। लेकिन इन उपायों से आप कर्ज को जल्द से जल्द से चुकता कर सकते हैं-

1. अगर आप कर्ज की प्रथम किश्त शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करते है तो शीघ्र आप त्र+ण से मुक्ति पा लेंगे।
2. घर का सारा कबाड़ अमावस्या या शनिवार को घर से बाहर करें।
3. मंगलवार को कभी क़र्ज़ न लें।
4. प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ स्फटिक श्री यंत्र के सामने करने से लक्ष्मी का आगमन होता है।
5. कभी भी बुधवार को क़र्ज़ न दें।
6. 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 5-5 पीस मीठे देसी घी के रोट का भोग लगाए।
7. व्यवसाय, मकान बनवाने हेतु कर्ज जन्मकुंडली की विवेचना करवाने के पश्चात लें।
8. प्रत्येक मंगलवार त्र+ण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
9. सुबह उठते ही सबसे पहले एक मुट्ठी चावल पंक्षियों को चुगने के लिए डालिए।
10. घर में कभी कोई भी मेहमान या अचानक कोई भी आए कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं नहीं तो पानी तो अवश्य ही पिलाएं।
11. शराब, मांस, नशे की चीजों से पूरी तरह से दूर रहें।

जीवन में रंगों को महत्व

कई लोगो को सादा जीवन पसंद है तो कईयों को रंगीन। क्या कभी आपने सोचा है कि इन रंग-बिरंगे रंगों को हमारे जीवन में क्या महत्व है। रंगों का हमारे जीवन व स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहा जाता हे कि रंग नेत्रों के माध्यम से हमारे मानस में प्रविष्ट होते हैं एवं हमारे स्वास्थ्य, चितन, आचार-विचार आदि पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः उचित रंगों का प्रयोग कर हम वांछित लाभ पा सकते हैं। किसी जातक की सफलता उसके कर्मों और कुछ हद तक लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करती है। वैसे तो प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व होता है लेकिन ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के दिनों का संबंध ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है।प्रत्येक दिन का एक नंबर होता है। उन रंगों का चयन करके अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। रंग हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं तथा हमारी सफलता व असफलता के कारक भी बनते हैं। शुभ रंग भाग्योदय कारक होते हैं और अशुभ रंग भाग्य में कमी करते हैं।

सोमवारः सफेद
मंगलवारः लाल
बुधवारः हरा
गुरुवारः पीला
शुक्रवारः सफेद
शनिवारः काला
रविवारः नारंगी

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

होर्मुज में 27 भारतीयों वाले जहाज पर हमला :इंजन रूम में आग लगी

होर्मुज, एजेंसी। होर्मुज में शुक्रवार को 27 भारतीय क्रू सदस्यों वाले तेल टैंकर एमटी लुईस 1 पर हमला हुआ। पनामा के झंडे वाले इस टैंकर पर दो लिम्पेट माइंस लगाई गई थीं। धमाके की वजह से इंजन रूम में आग लग गई और जहाज कुछ समय के लिए बंद हो गया। लेकिन क्रू ने आग बुझा दी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं लगी है। रॉयटर्स के मुताबिक, फरवरी में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद होर्मुज में पहली बार लिम्पेट माइंस से हमला हुआ है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी यूकेएमटीओ के मुताबिक, जहाज पर हमला ओमान के खासाब शहर से करीब 46 किलोमीटर दूर हुआ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से 27 अक्टूबर तक होर्मुज और उसके आसपास 120 समुद्री घटनाएं हुई। इनमें व्यापारिक जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के बाद ईरान पर फिर हमला कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, दोनों देश तेज सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ईरान के तेल-गैस ठिकानों, परमाणु केंद्रों और मिसाइलों-ड्रोन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।

सऊदी अरब में मिसाइल-ड्रोन हमलों के बीच अमेरिकी मिशन ने जारी की एक और एडवाइजरी

वाशिंगटन/रियाद, एजेंसी। सऊदी अरब में अहम ठिकानों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने मिशनों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने सभी गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों के परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। 30 अक्टूबर को अमेरिकी मिशन की ओर से जारी सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी अरब के खिलाफ हमलों और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन हमलों में नागरिक हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। इनके कारण आम नागरिकों की मौत और यात्रा व्यवस्था में गंभीर व्यवधान की घटनाएं हुई हैं। अमेरिकी मिशन ने आशंका जताई है कि मौजूदा शत्रुता तेजी से बढ़ सकती है और इसका प्रभाव संबंधित क्षेत्र से आगे भी फैल सकता है। एडवाइजरी के मुताबिक, सऊदी अरब में तैनात अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को हाल में हवाई अड्डों पर हुए मिसाइल और मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के हमलों के बाद देश के किसी भी हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने के लिए मिशन प्रमुख से विशेष अनुमति लेनी होगी। यूएस ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले, हवाई क्षेत्र बंद होने, उड़ानें रद्द होने और यात्रा में व्यवधान की आशंका बनी हुई है। अमेरिकी मिशन ने नागरिकों को सलाह दी है कि यदि वे सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतें। साथ ही यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी सीधे संबंधित एयरलाइन और हवाई अड्डे से प्राप्त करें। 10 अक्टूबर और फिर 25 अक्टूबर को रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत विभिन्न ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके बाद से कई बार अमेरिका अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी करता रहा है।

भारत-नेपाल सीमा पर सीसीटीवी ड्रोन और स्कैनर से होगी निगरानी, अवैध आवाजाही पर लगेगी रोक

काठमांडू, एजेंसी। भारत और नेपाल ने अपनी खुली सीमा की सुरक्षा मजबूत करने और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर सामान की जांच के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाने तथा निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर चर्चा की। शुक्रवार को दोनों देशों के सशस्त्र बलों की 10वीं समन्वय बैठक के समापन पर ये फैसले किए गए।प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर सामान की जांच के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल ने इसमें हिस्सा लिया। भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक संजय सिंघल ने भी बैठक में भाग लिया। यह बैठक बुधवार को काठमांडू स्थित एपीएफ मुख्यालय में शुरू हुई थी।

यूएन महासचिव की दौड़ में रेबेका ग्रिन्सपैन सबसे आगे, यूएई की लाना नुसीबेह नहीं बना सकीं बढ़त

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की प्रमुख रेबेका ग्रिन्सपैन संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव बनने की दौड़ में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच हुए सातवें अनौपचारिक मतदान में उन्हें पिछले दौर के मुकाबले दो अधिक सकारात्मक वोट मिले। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की विदेश मामलों की राज्य मंत्री लाना नुसीबेह अपनी पहली ही परीक्षा में कोई खास बढ़त हासिल नहीं कर सकीं। कोस्टा रिका की ग्रिन्सपैन को इस मतदान में 11 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ वोटों की संख्या घटकर चार रह गई। पिछले मतदान में उनके पक्ष में नौ और विरोध में पांच वोट मिले थे। इस तरह उन्होंने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया है और अब भी इस दौड़ में सबसे आगे हैं। सात दौर के मतदान में से छह में वह शीर्ष पर रही हैं। हालांकि, इस बार के मतदान में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ग्रिन्सपैन के खिलाफ पड़े चार वोटों में से कोई स्थायी सदस्य देश का था या नहीं। इसकी वजह यह है कि छठे दौर के विपरीत इस बार मतपत्रों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित नहीं किया गया था। पिछले दौर में ग्रिन्सपैन के खिलाफ पांच नवोट मिले थे, जिनमें दो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के थे। स्थायी सदस्य का विरोध किसी भी उम्मीदवार की राह में



बड़ी बाधा बन सकता है।

इस बीच, यूएई की ओर से पिछले सप्ताह उम्मीदवार घोषित की गई लाना नुसीबेह को पहली बार हुए मतदान में सात वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ छह मत पड़े और दो तटस्थ वोट डाले गए थे। वह कुल उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रहीं। उनसे आगे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख और अर्जेंटीना के राफेल ग्रॉसी दूसरे स्थान पर तथा गुयाना की पूर्व विदेश मंत्री कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट तीसरे स्थान पर रहीं।

ग्रॉसी के पक्ष में नौ, विरोध में चार और दो तटस्थ वोट मिले, जबकि रोड्रिग्स-बिर्केट को आठ सकारात्मक (पक्ष), छह नकारात्मक (विरुद्ध) और एक तटस्थ वोट मिला। मतदान की इस प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद के सदस्य तीन तरह से अपनी राय देते हैं। वे 'प्रोत्साहित' (एन्करेज), 'हतोत्साहित' (डिस्करेज) और 'कोई राय नहीं' (नो ओपिनियन) के विकल्प चुनते हैं। इन्हें क्रमशः सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ मत माना जाता है। अक्टूबर महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष रहीं ग्रीस की स्थायी प्रतिनिधि अग्लाया बाल्टा ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी की। उन्होंने औपचारिक रूप से परिणाम घोषित नहीं किए। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों पासब्लू और 1फॉर8बिलियन ने इन परिणामों का खुलासा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा पांच वर्षीय कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए महासचिव के चयन के लिए समय तेजी से निकल रहा है। बाल्टा ने भरोसा जताया कि सुरक्षा परिषद समय रहते महासभा को अपनी सिफारिश भेज देगी, ताकि नए महासचिव को पदभार संभालने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की योजना महासभा में नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर पूरी कराने के लिए अपनी सिफारिश उचित समय पर भेजने की है। अगले महीने लातविया सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और महासचिव के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके पास होगी। नए महासचिव के चयन में सुरक्षा परिषद की भूमिका निर्णायक है। किसी उम्मीदवार को कम से कम नौ सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा और पांच स्थायी सदस्यों में से किसी का भी विरोध नहीं होना चाहिए। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 सदस्य देशों की भागीदारी से महासचिव की नियुक्ति करती है। आमतौर पर महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश को मंजूरी दे देती है। फिलहाल परिषद के सदस्य बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों के बीच मतभेद कम किए जा सकें और किसी एक नाम पर सहमति बनाई जा सके। ग्रिन्सपैन के नकारात्मक वोटों में कमी और ग्रॉसी के समर्थन में बढ़ोतरी को इस बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

शुक्रवार के मतदान के बाद ग्रिन्सपैन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि दुनिया ऐसे निर्णायक दौर से गुजर रही है, जिसमें एकजुट और आधुनिक संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। उन्होंने सभी पक्षों की बात सुनने, जरूरी सुधारों को आगे बढ़ाने तथा शांति और सुरक्षा के साझा लक्ष्य को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बार महासचिव पद के चुनाव को लेकर एक महिला उम्मीदवार के चयन की मांग भी जोर पकड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के 80 साल से अधिक के इतिहास में अब तक नौ पुरुष इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन किसी महिला को यह जिम्मेदारी नहीं मिली है।

इजराइल के आम चुनाव की जांच खुफिया एजेंसी मोसाद करेगी

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हफ्ते हुए चुनाव में विदेशी दखल के आरोपों की जांच करेगी। न्यूज चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस जांच में आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट भी शामिल होगी। आरोप है कि कतर और कुछ दूसरे देशों ने मंगलवार को हुए चुनाव में अरब वोटर्स को पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश की। इस चुनाव में अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं। यह इतिहास में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी अरब पार्टियों पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इजराइल के केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जांच का दायरा सीमित है। आयोग के मुताबिक, इस मामले से चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही नतीजों पर सवाल उठता है।

यिस्त्राइल बेतेनु के चीफ बोले- अरब पार्टियों के साथ सरकार में शामिल नहीं होंगे : इजराइल की यिस्त्राइल बेतेनु पार्टी के चीफ एविगडोर लिबरमैन ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी ऐसी किसी सरकार में शामिल नहीं होगी, जिसमें उनके मुताबिक आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हों। लिबरमैन ने शुक्रवार को फेसबुक पर पोस्ट कर कई अरब और वामपंथी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को इसकी कीमत चुकानी चाहिए।

नेतन्याहू के बेटे बोले- ईरान के बाद इजराइल के लिए अरब नागरिक खतरा : इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने इजराइल के अरब नागरिकों को देश के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बाद इजराइली अरब नागरिक देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। द यरूशलम पोस्ट के मुताबिक, यायर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर चुनाव नतीजों को लेकर यह बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि वेस्ट बैंक और गाजा के फिलिस्तीनियों, तुर्किये और पश्चिमी देशों में बढ़ते यहूदी-विरोध से भी बड़ा खतरा इजराइल के अरब नागरिकों से है। यायर ने लिखा कि इजराइल लंबे समय तक ऐसे हालात में नहीं टिक सकता, जहां उसकी 20% आबादी उसके दुश्मनों का समर्थन करती हो और देश का विनाश चाहती हो।

इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दल यूनाइटेड टोरा जूडिज्म ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी को चुनाव में 7 सीटें मिली हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी ने समर्थन के बदले हरेदी समुदाय के लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग की है। इजराइल में आमतौर पर नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है। हालांकि, हरेदी समुदाय के धार्मिक छात्रों को अब तक इससे बड़े स्तर पर छूट मिलती रही है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने काजा कैलास से यूक्रेन और खाड़ी संघर्ष पर चर्चा की

अटलांटा, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए ईयू की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास से मुलाकात की और वैश्विक संघर्षों पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ईयू एचआरवीपी काजा कैलास के साथ यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी की स्थिति पर चर्चा की।' विदेश मंत्री ने आखिरी बार यूरोपीय संघ के नेता के साथ 25 अक्टूबर को राजनयिक पदों पर समन्वय के लिए फोन पर बात की थी, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

इस बीच, काजा कैलास ने जी20 बैठक के पहले पूर्ण सत्र में अपनी टिप्पणी के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण उत्पन्न संकट पर भी प्रकाश डाला। कैलास ने एक्स पोस्ट में कहा, 'यूक्रेन पर रूस का हमला और मध्य पूर्व संकट ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति, व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। समुद्री मार्ग वैश्विक जीवन रेखाएं हैं।' उन्होंने कहा, 'अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में, मैंने काला सागर में नेविगेशन स्वतंत्रता की व्यवस्था का आह्वान किया और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर टोल और शुल्क के लिए यूरोपीय संघ के विरोध की पुष्टि की।' ईयू एचआरवीपी ने कहा, 'ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।' इससे पहले, सत्र में अपनी टिप्पणी के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के समय कूटनीति के महत्व पर भारत के रुख को भी दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य समाधान वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं करेंगे और कूटनीति को एक मौका दिया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ शिपिंग पर हमलों के लिए असंगत कीमत चुका रहा है।

साख बचानी है तो छोड़े दोहरा रवैया': भारत की यूएनएचआरसी को खरी खरी

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भारत का पक्ष रखा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी साख तभी बनी रह सकती है, जब वह सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। किसी देश को शामिल किए बिना उसके खिलाफ विशेष आदेश जारी करने से जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं आता। इससे परिषद के भीतर मतभेद जरूर बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर किसी देश को निशाना बनाना या दोहरे मापदंड अपनाना सही तरीका नहीं है।

बातचीत और सहयोग से आगे बढ़ेंगे मानवाधिकार : भाविका मंगलानंदन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के फरवरी में दिए गए बयान का भी जिक्र किया। जयशंकर ने मानवाधिकार परिषद के 61वें उच्चस्तरीय सत्र में कहा



था कि मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपसी बातचीत, क्षमता बढ़ाने में मदद और सच्ची साझेदारी है। इसके बजाय राजनीतिक फायदे के लिए मानवाधिकारों का इस्तेमाल करना और चुनिंदा देशों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। भारत का मानना है कि अगर परिषद को एकजुट होकर काम करना है, तो उसे उन आरोपों से बचना होगा, जिनमें कहा जाता है कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

सभी देशों के लिए एक जैसा नियम हो : भारत ने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू को मानवाधिकारों पर चर्चा का बेहतर मंच बताया। इस व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा होती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें हर देश को बराबर माना जाता है और बातचीत के जरिए सुधार पर जोर दिया जाता है। भारत इस साल 2026-28 के कार्यकाल के लिए सातवीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। आतंकवाद को बताया मानवाधिकारों के लिए बड़ा खतरा भारत ने आतंकवाद को मानवाधिकारों के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया। खासतौर पर जीवन के अधिकार पर इसके खतरे को रेखांकित करते हुए परिषद से अपील की गई कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और इस मुद्दे पर लगातार ध्यान दे। विकास के अधिकार को भी मिले बराबर महत्व भारत ने कहा कि मानवाधिकारों को अलग-अलग नजरिए से देखने के बजाय सभी अधिकारों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की तरह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ विकास के अधिकार को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत ने बताया कि विकासशील देशों में गरीबी, बढ़ता कर्ज और आर्थिक संसाधनों व नई तकनीक तक सीमित पहुंच लोगों के अधिकारों के रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। इन समस्याओं का समाधान दबाव बनाकर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही निकाला जा सकता है। भारत ने यह भी कहा कि मानवाधिकार परिषद को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ही काम करना चाहिए। परिषद में सुधार की प्रक्रिया सदस्य देशों की अगुवाई में और पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। इस दौरान विकास और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े काम प्रभावित नहीं होने चाहिए। भारत ने मानवाधिकारों से जुड़े कामों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से पर्याप्त धन देने की मांग भी की।

हूती विद्रोहियों ने यमन के राष्ट्रपति भवन पर मिसाइलें दागीं

सना, एजेंसी। यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को अदन में राष्ट्रपति भवन पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि मिसाइलें अपने निशाने पर लगीं या नहीं। न्यूज एजेंसी ⁄ख़बक के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन की ओर एंबुलेंस जाते हुए देखी गईं। यमन सरकार के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने अदन एयरपोर्ट पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि, उन्होंने हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति भवन पर 15 दिन में यह दूसरा हमला है। इससे पहले 15 अक्टूबर को हुए हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के मदीना इलाके की ओर भी ड्रोन भेजा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इसे हवा में ही मार गिराया।



अदन यमनी सरकार का हेडक्वार्टर : अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का प्रमुख केंद्र है। हूती विद्रोहियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सरकार को सना छोड़ना पड़ा था। जुलाई से अदन में हमले फिर बढ़े हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर को भी हूती विद्रोहियों ने अदन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। हमले से पहले हूतियों ने लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। यह एयरपोर्ट दक्षिणी यमन में राहत सामग्री और मानवीय मदद पहुंचाने का अहम रास्ता है।

सऊदी का मक्का और मदीना में ड्रोन रोकने का दावा : सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने शुक्रवार को मदीना के ऊपर एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इससे पहले गठबंधन मक्का में भी एक ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर चुका है। मक्का में ग्रैंड मस्जिद और काबा हैं, जबकि मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद है। दोनों शहर मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में शामिल हैं। सऊदी अरब ने अक्टूबर में हूती विद्रोहियों पर मदीना के बिजली वितरण केंद्र पर हमला करने का आरोप लगाया था। यह केंद्र पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद को बिजली की आपूर्ति करता है। हालांकि, हूतियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। हूती मक्का और मदीना को निशाना बनाने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि वे सऊदी अरब के सैन्य और तेल से जुड़े ठिकानों पर हमले करते हैं। सऊदी अरब यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है।

यूक्रेन को बड़ी राहत: 500 पैट्रियट मिसाइलें देगा अमेरिका, जेलेंस्की बोले- सर्दियों से पहले मिलें हथियार

कीव, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए अमेरिका की ओर से 500 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे 'मजबूत फैसला' बताया, लेकिन अमेरिका से इन मिसाइलों की आपूर्ति जल्द शुरू करने की अपील की है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को सर्दियों में ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा के लिए तुरंत इन मिसाइलों की जरूरत है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 500 पीएसी-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार काफी बड़ा है। सर्दियों के दौरान यह यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा शर्तों के मुताबिक इन मिसाइलों की आपूर्ति कुछ वर्षों बाद ही शुरू हो सकती है।

रूस के हमलों पर क्या बोले जेलेंस्की : उन्होंने कहा, 'हम अपने अमेरिकी साझेदारों से ऐसा समाधान तलाशने की अपील कर रहे हैं, जिससे पीएसी-3 इंटरसेप्टर की आपूर्ति उस समय हो सके, जब वास्तविक खतरा हो और उनकी जरूरत हो।' उन्होंने बताया कि रूसी सेना रोजाना यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रही है। जेलेंस्की के मुताबिक, अक्टूबर के पिछले दो हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के बिजली ग्रिड के महत्वपूर्ण हिस्सों पर 30 से ज्यादा हमले किए। उन्होंने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सर्दियों से पहले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी



व्यवस्थाओं को ठप करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इन हमलों का निशाना बिजली, हीटिंग, पानी की आपूर्ति और पुल हैं।

हर महीने मिलें 100 पैट्रियट मिसाइलें : यूक्रेनी राष्ट्रपति : यूक्रेन ने सर्दियों के लिए हर महीने औसतन 100 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि 500 मिसाइलें आने वाले महीनों में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहम होंगी। इस दौरान यूक्रेन के लिए बातचीत में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना भी जरूरी है। तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका, यूरोपीय साझेदारों और अन्य सहयोगी देशों से अपने मौजूदा भंडार से मिसाइलें देने का प्रस्ताव रखा है। उनका सुझाव है कि 2026-27 की सर्दियों में यूक्रेन को इन भंडारों से मिसाइलें दी जाएं और बाद में नए उत्पादन के जरिए सहयोगी देशों के हथियार भंडार की भरपाई की जाए। उन्होंने कहा, 'हम इस मंजूरी के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और पूरे अमेरिकी प्रशासन के आभारी हैं। लेकिन हम ऐसे फैसले चाहते हैं, जो लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

कनाडा बनेगा यूरोपीय संघ का पहला 'एसोसिएट सदस्य'

मॉन्ट्रियल/वाशिंगटन, एजेंसी। कनाडा और यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने संबंधों को नया आयाम देते हुए नई दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दोनों पक्ष कनाडा को यूरोपीय संघ का पहला 'एसोसिएट सदस्य' बनाने की दिशा में काम करेंगे। यह व्यवस्था पूर्ण सदस्यता से एक कदम पीछे होगी, लेकिन इसके तहत कनाडा को यूरोपीय संघ के साथ व्यापक आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी और रक्षा सहयोग का अवसर मिलेगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि कनाडा और यूरोपीय संघ पूर्ण सदस्यता से इतर सबसे गहरी साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत कनाडा यूरोपीय संघ का पहला एसोसिएट सदस्य बन सकता है।

कार्नी ने कहा, 'मॉन्ट्रियल में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने 20 से अधिक नए उपायों पर सहमति बनाई है। इनका उद्देश्य अटलांटिक के दोनों ओर आर्थिक अवसरों को बढ़ाना, लोगों के लिए चीजों को अधिक किफायती बनाना और अपनी संप्रभुता को मजबूत करना है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यूरोपीय संघ-कनाडा शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने पूर्ण सदस्यता के अलावा हर



संभव क्षेत्र में नजदीकी सहयोग के लिए सहमति बनाई है।

कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, आने वाले महीनों में दोनों पक्ष इस नई सदस्यता व्यवस्था के स्वरूप, दायरे और विषयों को अंतिम रूप देंगे। 21वां कनाडा-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 29 और 30 अक्टूबर को मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री कार्नी के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल हुईं। सम्मेलन के बाद दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान भी जारी किया। इस दौरान व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। कनाडा और यूरोपीय संघ ने डिजिटल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया और प्रतिस्पर्धा से जुड़े समझौते पर बातचीत पूरी की। इसके अलावा कनाडा यूरोपीय हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ज्वाइंट अंडरटेकिंग में शामिल हुआ है। इससे कनाडा के शोधकर्ताओं को यूरोप के अत्याधुनिक जुपिटर सुपरकंप्यूटर तक पहुंच मिलेगी। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा ने एक ऐसी संधि रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूरोपीय निवेश बैंक कनाडा की महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा। दोनों पक्ष यूरोप को कनाडा से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक नई ट्रांसअटलांटिक डेटा केबल बिछाने पर भी विचार किया जाएगा। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कनाडा की भागीदारी बढ़ाने की योजना है। कनाडा यूरोपीय संघ के इरास्मस प्लस कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी और अगले होराइजन यूरोप अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बातचीत करेगा। रक्षा सहयोग के मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। कनाडा ने यूरोपीय संघ की 'सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप' (सेफ) पहल के तहत अपना दूसरा अनुबंध हासिल किया है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नोएडा एनकाउंटर में मारा गया 50 हजार का इनामी अमन त्यागी

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-126 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमन त्यागी मारा गया। पुलिस ने बताया कि त्यागी रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी तथा गैंगस्टर एक्ट सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में गोली लगने से दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सेक्टर-126 थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी कि तभी बाइक सवार एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर भागने लगा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर जिले के छपार गांव निवासी अमन त्यागी के रूप में हुई है।

पंजाब में आप को दोहरा झटका : दो विधायकों ने छोड़ी पार्टी

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो विधायकों, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा, ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम ने आप के चुनावी समीकरणों पर सवाल खड़े किए हैं। हरमीत सनौर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि चेतन सिंह जौरामाजरा समाना सीट से विधायक थे। दोनों विधायकों ने अलग-अलग तरीकों से पार्टी छोड़ने की घोषणा की। हरमीत सिंह ने अपना इस्तीफा सीधे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा और तत्काल प्रभाव से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वहीं, पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके चेतन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सदस्यता त्यागने की जानकारी दी। उन्होंने पंजाब में आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा को संबोधित कर अपना इस्तीफा भेजा। यह इस्तीफा तब आया है जब आप ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। हालांकि, इस सूची में सनौर और समाना सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए थे, जिन पर अब ये दोनों विधायक काबिज नहीं रहे। इस घटनाक्रम से पंजाब में आप की चुनौतियां बढ़ने की संभावना है।

आजम खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, ईडी रिमांड की तैयारी में

लखनऊ, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल ले जाया जाएगा। यह फैसला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई के बाद आया है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आजम की रिमांड लेने की तैयारी में जुटा है। ईडी सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अगले एक-दो दिनों में पीएमएलए कोर्ट में उनकी पुलिस कस्टडी (पीसी) रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है। यदि अदालत रिमांड देती है, तब ईडी उन्हें लखनऊ ले जाकर जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग और कथित मनी ट्रेल के संबंध में गहन पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि रविवार को हुई सुनवाई के दौरान, ईडी ने अदालत से आजम की 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी। जांच एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) को लेकर अपनी दलीलें पेश कीं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग में किस तरह की कथित अनियमितताएं हुई हैं, जिसके आधार पर उन्होंने हिरासत की मांग की थी।

अखिलेश का शाह पर पलटवार: जमीन ही नहीं... पैर कहां रखोगे?

राज्य में 1 लाख 27 हजार हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए

नई दिल्ली , एजेंसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित वोट चोरी के खिलाफ रैली को संबोधित कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अंगद के पैर वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, जो लोग अंगद का पैर कहने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब जमीन ही नहीं बची है तब पैर कहां रखेंगे?

अखिलेश यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधकर आरोप लगाया कि देश में एक करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दावा किया कि राज्य में 1 लाख 27 हजार हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिससे हर विधानसभा में करीब 31 हजार वोटों की कमी हुई। सपा मुखिया ने कहा कि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी वाले उन्हें करारा जवाब देकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे।



सपा प्रमुख ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का उल्लेख किया, जहां उन्होंने वोट लूटे जाने और चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार न बनने का कारण भी वोट चोरी थी। अखिलेश ने भाजपा पर कटाक्ष कर कहा कि जो लोग विश्वगुरु बनने की बात करते थे, वे मतदाता सूची में चोरी करते हैं।

सपा नेता यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन रुकने वाला नहीं है और लोकतंत्र को बचाने का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। उन्होंने रामलीला मैदान को लोकतंत्र की हल्दीघाटी करार देकर कहा कि यहां से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और परिवर्तन कभी भी आ सकता है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि अगली पीढ़ी भाजपा द्वारा लगाए गए हर लाठी और दिए गए हर जख्म का बदला लेगी, जिससे भाजपा खुद को बचा नहीं पाएगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के डबल इंजन सरकार के दावे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष कर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि काशी की जनता ने एमएलसी चुनाव में भाजपा को डबल जीरो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चंडीगढ़ जैसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन असफल रही। अखिलेश ने भाजपा पर लगातार साजिशें और षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर कहा कि वे जनता के बीच में नहीं जीत सकते, इसलिए चुनाव के माध्यम से हेरफेर का रास्ता अपनाते हैं।

एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस राज्यों में अलग-अलग रुख अपना रही

- दिल्ली में रैली से पहले ओवैसी ने नीतियों और नीयत पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित विशाल रैली से ठीक पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने मतदाता सूची एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की नीतियों और नीयत पर सवाल उठाते हुए उस पर दोहरा रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रुख अपना रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री सतीश जारकीहोली एसआईआर की तारीफ कर रहे हैं और इसे बेहतर बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के अन्य नेता इसका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्पष्ट नीति नहीं है और देश के अलग-अलग हिस्सों में उसके नेता अलग-अलग धुन बजा रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन हैदराबाद में उसके स्थानीय नेता खुद चुनाव आयोग के पास जाकर मतदाताओं के नाम हटाने की मांग करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी का अपना रुख स्पष्ट नहीं है, तो वह जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ रैली कर रही है। उधर, दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी रैली को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्र में 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 270 कंपनियों को तैनात किया गया है। पूरे रूट पर नजर रखने के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षाबलों ने मिंटो रोड से लेकर रामलीला मैदान तक कड़ा पहरा लगा रखा है ताकि रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर गुवाहाटी तक विस्तारित, मिली केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र की सरकार ने प्रस्तावित दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को हरी झंडी मिलने की जानकारी दी। सीएम सरमा ने निर्णय का जश्न मनाकर लिखा, इसीलिए, मोदी कहीं नहीं जाएंगे! यह टिप्पणी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर हुई बहस का तीखा जवाब थी, जिसमें एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द पद न छोड़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताकर कहा कि गुवाहाटी और दिल्ली के बीच यात्रा आठ घंटे से भी कम समय में पूरी होगी। उन्होंने इस मंजूरी को पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। सीएम सरमा ने बताया कि यह कॉरिडोर शुरू में सिलीगुड़ी में समाप्त होना था, लेकिन उनके अनुरोध और जुलाई में केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात के बाद, केंद्र ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर पूर्वोत्तर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, जो सरकार सुनती है और काम करती है, वह ऐसी ही दिखती है। इस परियोजना से असम को नई हाई-टेक इंडस्ट्रीज के विकास और दिल्ली व अन्य राज्यों की राजधानियों से तेज व सस्ती कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार तथा रोजगार के मौकों में वृद्धि होने की उम्मीद है। सीएम सरमा ने कहा कि बुलेट ट्रेन जो कभी असम के लिए दूर का सपना थी, अब हकीकत बन रही है। उन्होंने 7 जून को रेल मंत्री वैष्णव को लिखे पत्र में गुवाहाटी को नॉर्थईस्ट का गेटवे और इलाके का सबसे बड़ा आर्थिक व परिवहन हब बताकर कॉरिडोर के विस्तार की अपील की थी। इसके पहले, केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के उत्तरी गलियारे को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली से शुरू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगा, और फिर वाराणसी व पटना से होकर गुवाहाटी तक पहुंचेगा।

मुरासु का खौफ: आंध्र तट पर भारी तबाही की आशंका

अमरावती, एजेंसी । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 1 नवंबर 2026 को दोपहर 11:30 बजे पुष्टि की कि दक्षिण-पश्चिम और आसपास के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित गहरा डिप्रेशन अब चक्रवाती तूफान 'मुरासु' में बदल गया है, मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में खौफ पैदा कर दिया है। यह तूफान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके 2 नवंबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की प्रबल संभावना है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 'मुरासु' 2 नवंबर की मध्य रात्रि से 3 नवंबर की सुबह के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकते हैं।



1 नवंबर दोपहर को यह तूफान चेन्नई से करीब 560 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था और लगातार मजबूत हो रहा है। यह उन इलाकों के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा जो हाल ही में चक्रवात अर्नब के असर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में 2 और 3 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के तारों को नुकसान पहुंचने और निचले इलाकों में व्यापक बाढ़ का खतरा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है, और स्थानीय प्रशासन ने संभावित आपदा से निपटने के लिए बचाव एवं राहत कार्य की तैयारियां तेज कर दी हैं।

इस चक्रवाती तूफान का नाम 'मुरासु' भारत द्वारा सुझाया गया है। तमिल भाषा में 'मुरासु' का अर्थ है प्राचीन ढोल, जिसका उपयोग पुराने समय में गांवों में महत्वपूर्ण जानकारी फैलाने और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देने के लिए किया जाता था। आईएमडी द्वारा यह नाम तब दिया जाता है जब सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी में पहुंच जाता है, जो वर्तमान खतरे की गंभीरता को दर्शाता है।

सीजेपी की दिवाली पार्टी में पहुंचे कई विपक्षी नेता, बढ़ रही विपक्ष से नजदीकियां

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच नजदीकी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को सीजेपी नेता सौरव दास की ओर से आयोजित दीपावली पार्टी में टीएमसी, माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-(एसपी) समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-(एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर पोस्ट कर अभिजीत दीपके, सौरव दास और उनकी टीम का आभार जताया। उन्होंने लिखा- शानदार दिवाली शाम के लिए अभिजीत दीपके, सौरव दास और पूरी टीम का धन्यवाद। इस आयोजन को सीजेपी नेताओं और विपक्ष के एक वर्ग के बीच बढ़ते संपर्क के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका भी दिवाली पार्टी में मौजूद रहे। सीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकी का यह अकेला उदाहरण नहीं है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सीजेपी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के समर्थन में कई बार बयान दिए हैं। सीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। दोनों पक्षों के बीच संपर्क बढ़ने की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर हुई सार्वजनिक बयानबाजी से मानी जा रही है। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ समानांतर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की थी। वहीं सीजेपी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को होने वाली रैली को समर्थन दिया, हालांकि इसमें सीजेपी कार्यकर्ता शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश के बाद सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था- जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल में डालना कायरता है। राहुल गांधी ने अपने एक अन्य संदेश में छात्रों, युवाओं, पत्रकारों और इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा था कि अलग-अलग बैनर के बावजूद सभी का मकसद एक ही है, उनके मुताबिक, ये प्रदर्शन नागरिकों के अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा था कि जंतर-मंतर भारत के लोगों का है और वे इसे वापस हासिल करेंगे।

नड्डा का इंडिया गठबंधन पर हमला: कांग्रेस के पाप में सहभागिता पर उठाए सवाल

इंडिया गठबंधन की रैली कांग्रेस पार्टी के पतन के ताबूत में आखिरी कील

नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन की हालिया मेगा रैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से सीधे सवाल किया है कि क्या वे भी कांग्रेस पार्टी के उस पाप में शामिल हैं, जिसमें हमारे सिख भाइयों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था? केंद्रीय मंत्री नड्डा ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करने के पाप में भी कांग्रेस भागीदार है, और अब इंडिया गठबंधन के सदस्य इस देश के लोगों से नफरत करने लगे हैं, सिर्फ भाजपा के प्रति अपनी गहरी नफरत के चलते है।

बीजेपी नेता नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाकर कहा कि वे विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं और देश में आकर भारत के लोकतंत्र तथा अर्थव्यवस्था पर हमला करते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी का एकमात्र मकसद देश का विकास नहीं, बल्कि अराजकता और तबाही फैलाना है। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देकर कहा कि भारत की जनता अब उनके धोखे में नहीं आने वाली, क्योंकि अराजकता फैलाने के लिए उनकी टूलकिट पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने राहुल गांधी को 1 नवंबर के काले इतिहास और दिल्ली के व्यापारियों के आंसूओं के लिए अपनी जवाबदेही से न बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, जहां संविधान और जनता का जनादेश चलेगा, न कि दंगा-भड़काने वाली राजनीति कामयाब होगी। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भविष्यवाणी की कि इंडिया गठबंधन की यह रैली कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इससे पहले भी, जेपी नड्डा राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं, जैसे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, को कमजोर करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव जीतने पर अपनी काबिलियत का बखान करते हैं, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग को दोष देते हैं, जो



उनकी राजनीति की एक चिर-परिचित शैली बन गई है।

सीएम फडणवीस का कांग्रेस पर करारा हमला: आपातकाल में हुई थी संविधान चोरी

मुंबई , एजेंसी । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार कर सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर आपातकाल के दौरान संविधान चोरी करने और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। ठाणे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ मार्च को संबोधित कर उन्होंने दावा किया कि जो लोग वोट चोरी का शोर मचाते हैं, असल में वे ही संविधान चोर हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र ने वर्ष 1975 के आपातकाल का जिक्र कर कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, कांग्रेस सरकार ने न्यायपालिका को उनके चुनाव की जांच करने से रोकने के लिए पूर्वव्यापी संवैधानिक संशोधन लाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही वह पहली पार्टी थी जो कि संविधान, न्यायपालिका और देश के लोकतंत्र को कमजोर किया। फडणवीस ने 42वें संविधान संशोधन का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित तरीके से मौलिक अधिकारों की



सुरक्षा करने वाले प्रावधानों को कमजोर कर दिया था, जिन्हें 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद बहाल किया गया।

सीएम फडणवीस ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय ताकतें और सोशल मीडिया एल्गोरिदम देश में अराजकता फैलाने के लिए गलत सूचनाएं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष की चिंता पर निशाना साधकर कहा कि भाजपा अंतिम घुसपैठिए का नाम हटाए जाने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का उल्लेख कर कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आदर्शों के लिए बलिदान की समृद्ध परंपरा रही है। सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र बचाओ मार्च एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है और पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण तक नहीं रुकेगी।

हिंसा के खिलाफ इंफाल में उमड़ा जनसैलाब, दी फाइनल वॉर्निंग

इंफाल, एजेंसी । मणिपुर के नोने जिले में हाल ही में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत और जारी हिंसा के विरोध में राजधानी इंफाल की सड़कों पर शनिवार को हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (कोकोमी) और विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के आह्वान पर निकाली गई इस विशाल महारैली में राज्य के घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार को फाइनल वॉर्निंग देते हुए मांग की है कि यदि सरकार राज्य में पूरी तरह शांति बहाल करने में असमर्थ है, तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्वाकीथेल स्थित टिडिम ग्राउंड से शुरू हुई इस रैली का उद्देश्य लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करना और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना था।

राहुल गांधी के बुलावे पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज: मोदी जी ने बुलाया, तब मैं क्या करूं?

मुंबई, एजेंसी । शिवसेना (यूबीटी) की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी राजनीतिक यात्रा, कांग्रेस में वापसी की संभावना और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर खुलकर बात की। जब प्रियंका से पूछा गया कि अगर राहुल गांधी उन्हें फोन करके कांग्रेस में वापस आने को कहें, तब उनका जवाब क्या होगा, तब प्रियंका ने एक दिलचस्प और तंज भरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं पूछूंगी कि मोदी जी ने बुलाया तब मैं क्या करूं? यह बयान राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बन गया है।

कांग्रेस छोड़ने के अपने पुराने फैसले पर उन्होंने कहा कि एक समय था जब उनके लिए पार्टी में स्थितियां काफी नकारात्मक हो गई थीं और उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर भी निराशा महसूस होने लगी थी। उन्होंने जोड़ा कि कुछ लोगों का उनसे जुड़ा जुनून अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देकर कहा कि वह हमेशा काम करते रहने और खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखती हैं। युवाओं से जुड़ने की भाषा के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी की कि कई बार नेता जेन-जी की भाषा का इस्तेमाल कर कूल दिखने की



कोशिश करते हैं जो अजीब और क्रिंज लग सकता है। उनका मानना है कि युवाओं से जुड़ने के लिए जबरदस्ती उनकी भाषा बोलना जरूरी नहीं है।

महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन और पार्टी के विभाजन पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी को कोई ऑफर मिलता है और वह उस स्वीकार कर लेता है, तब यह दर्शाता है कि पूरा घटनाक्रम पहले से ही सुनियोजित था। उन्होंने अपनी पार्टी के संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास पर जोर दिया और सुप्रीम कोर्ट को जलाने जैसी हिंसात्मक बयानबाजी का विरोध किया। इंटरव्यू के दौरान, हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने खुद को रील बनाने में नंबर वन बताया और अपनी जिंदगी पर फिल्म बनने पर मैं अपनी फेवरेट हूं शीर्षक चुना।